A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 18 मार्च, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 194, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

अपने होंटों पर सजाना चाहता हूँ
आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ

कोई आँसू तेरे दामन पर गिरा कर
बूँद को मोती बनाना चाहता हूँ

थक गया मैं करते करते याद तुझ को
अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ

छा रहा है सारी बस्ती में अँधेरा
रौशनी को, घर जलाना चाहता हूँ

आख़री हिचकी तिरे ज़ानू पे आए
मौत भी मैं शाइ'राना चाहता हूँ

– क़तील शिफ़ाई

प्रसंगवश

ईरान जंग से 'इस्लामी नेटो' को फिर हवा, क्या ये संभव है?

मुन्जा अनवर

ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बीच क़तर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी का एक सुझाव चर्चा में है। अल थानी ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों को तुरंत अपने मतभेद ख़त्म कर 'नेटो' की तर्ज़ पर एक प्रभावी सैन्य और सुरक्षा गठबंधन' बनाने का सुझाव दिया है। जिसमें 'सऊदी अरब केंद्रीय भूमिका निभाए और पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरा सहयोग हो।' इससे पहले मुस्लिम गठबंधन बनाने का विचार सितंबर 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैय्यप अर्दोआन ने पेश किया था। वहीं, सितंबर 2025 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी 'इस्लामी नेटो' के गठन की मांग की थी।

साल 2017 में सऊदी अरब के नेतृत्व में बने 34 इस्लामी देशों के सैन्य गठबंधन की कमान पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ़ को सौंपी गई थी। तब ईरान ने इस गठबंधन का नेतृत्व जनरल राहील शरीफ़ को सौंपे जाने पर गहरी चिंता और आपत्ति जताई थी। उस समय भी खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय हितों के टकराव की वजह से इस गठबंधन पर सवाल उठे थे। ये अब भी मौजूद हैं और किसी भी नए गठबंधन के रास्ते में बड़ी बाधा हैं। यमन के मुद्दे पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मतभेद और क़तर और अमीरात के बीच अतीत का तनाव इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 'गल्फ़ नेटो' के गठन की सोच किस हद तक सच हो सकती है और इसमें क्या रुकावटें आ सकती हैं?

जीसीसी के नेतृत्व में एक सैन्य और रक्षा औद्योगिक आधार बनाने का लक्ष्य कितना व्यावहारिक है और इस पर अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? और अगर खाड़ी देश तुर्की और पाकिस्तान के साथ सैन्य और रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहें तो पाकिस्तान वास्तव में किस हद तक यह भूमिका निभा सकता है? क़तर के पूर्व प्रधानमंत्री ने राजनीतिक और सैन्य गठबंधन के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'हमे वर्तमान युद्ध से सबक़ और सीख लेना ज़रूरी है। गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल को एकता और एकजुटता के साथ एक प्रभावी और वास्तविक सैन्य और सुरक्षा गठबंधन बनाना होगा, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन यानी नेटो है। इसमें 'सऊदी अरब को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि वह सबसे बड़ा देश है।' अल थानी ने कहा कि अब युद्ध समाप्त होने का इंतज़ार किए बिना तैयारी शुरू की जाए और मतभेद ख़त्म किए जाएं ताकि जनता को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने ईरान का उदाहरण देते हुए कहा, 'पाबंदियों के बावजूद उसने मिसाइल इंडस्ट्री लगाई और अफ़सोस कि उन्हीं मिसाइलों से खाड़ी देशों को निशाना बनाया गया।'

हमद बिन जासिम ने सुझाव दिया कि खाड़ी देश इसराइल और ईरान दोनों के ख़िलाफ़ एकजुट हों। ईरान पड़ोसी है, इसलिए उसके साथ बातचीत के लिए स्पष्ट रणनीति ज़रूरी है जबकि इसराइल के साथ संबंध अच्छे पड़ोस और फ़लस्तीनी अधिकारों के संरक्षण के आधार पर होने चाहिए।' आख़िर में उन्होंने कहा कि गल्फ़ काउंसिल के देशों पर हमलों के बावजूद कई अरब देशों की चुप्पी ताज्जुब की बात है। यही स्थिति खाड़ी देशों को तुरंत एक सैन्य, सुरक्षा और भौगोलिक गठबंधन बनाने पर मजबूर करती है जो तुर्की और पाकिस्तान के साथ मज़बूत संबंध रखे लेकिन अपने 'धरती पुत्रों' पर भी भरोसा करे। '

हमद बिन जासिम के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। जेद्दाह में रहने वाले पत्रकार सालेह अल-फ़हीद ने सवाल किया, 'ऐसे में सहमति और गठबंधन कैसे संभव है जब छोटे देश बड़े देश से नेतृत्व छीनने की कोशिश करते हैं? एकजुटता और समझौता कैसे हो जब छोटे देश बड़े के ख़िलाफ़ नफ़रत और हस्तक्षेप की नीति पर अड़े रहते हैं? '

सऊदी अरब, यूएई और कतर के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के मद्देनज़र 'गल्फ़ नेटो' के गठन की सोच कितनी सच हो सकती है और कौन सी बड़ी चुनौतियां इसके रास्ते में बाधा बन सकती हैं? मेहरान कामराफ़ा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, क़तर में प्रोफ़ेसर और अरब सेंटर फ़ॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ में रिसर्च यूनिट के डायरेक्टर हैं। उनके अनुसार, 'इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब भी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) किसी संकट का सामना करती है तो यह एकजुट होकर एक इकाई की तरह काम करती है। बाहरी दुनिया की नज़र में जीसीसी तब बनी जब ईरान-इराक युद्ध हुआ। संकट के दौरान यह एक एकीकृत इकाई की तरह काम करती है। लेकिन जब बाहरी संकट कम हो जाता है तो जीसीसी का रवैया बदल जाता है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर जीसीसी अपने सदस्यों की सुरक्षा, आर्थिक अस्तित्व और सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई क़दम उठाए। '

साइमन वोल्फ़गांग फ़ुक्स, यरूशलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में 'दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में इस्लाम' के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उनके अनुसार, 'इसमें कोई शक नहीं कि यह अमेरिका की भी परोक्ष आलोचना है जिसने खाड़ी देशों को अकेला छोड़ दिया, उन्हें पहले इसकी कोई जानकारी या वॉर्निंग नहीं दी और युद्ध के दौरान उन्हें एयर डिफ़ेंस सिस्टम फिर से सप्लाई करने के लिए भी वह तैयार नहीं था। खाड़ी देश इस भरोसे थे कि वह 'स्थिरता के द्वीप' हैं और अपने चारों ओर ईरान, इराक, सीरिया, यमन, इसराइल और फ़लस्तीन के संघर्षों से खुद को अलग रख सकते हैं। 'सऊदी अरब और यूएई के बीच हावी होने की उलझन ख़त्म नहीं हो सकती। सैन्य रूप से सऊदी सेना यूएई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कुल मिलाकर 'गल्फ़ नेटो' गंभीर मतभेदों के कारण संभव नहीं। '

जीसीसी के नेतृत्व में सैन्य और रक्षा औद्योगिक आधार बनाने का लक्ष्य कितना वास्तविक है और अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? इसके बारे में साइमन वोल्फ़गांग फ़ुक्स का मानना है कि औद्योगिक आधार का मामला भी पेचीदा है। 'खाड़ी देशों के पास कोई वास्तविक औद्योगिक आधार नहीं है। खाड़ी की सेनाएं अमेरिकी हथियारों पर निर्भर रहती हैं।' प्रोफ़ेसर मेहरान कामराफ़ा का मानना है कि अगर खाड़ी देश तुर्की और पाकिस्तान के साथ सैन्य और रक्षा सहयोग को और गहरा करना चाहें तो पाकिस्तान क्या भूमिका निभा सकता है?

उमर करीम का कहना है कि खुद आधुनिक सैन्य तकनीक व हथियारों के लिए वह चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। दूसरी ओर तुर्की के पास तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एडवांस्ड औद्योगिक आधार है और वह खाड़ी देशों के साथ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकता है। फ़ुक्स कहते हैं, अब सऊदी अरब ने अपनी सेना में भारी निवेश किया है।उसे पाकिस्तानी सैनिकों पर निर्भर रहने की वैसी ज़रूरत नहीं रही। '

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बच्चे को गोद लेने वाली मां भी मैटरनिटी लीव की हकदार

- एससी का बड़ा फैसला, अभी उम्र 3 महीने से कम होना जरूरी था

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- अब पितृत्व अवकाश पर भी कानून बने

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि गोद लिए गए बच्चे की उम्र 3 महीने से अधिक होने पर मैटरनिटी लीव से इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बच्चा गोद लेने पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी व्यवस्था, जिसके तहत तीन महीने से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता, असंवैधानिक है। बच्चे की उम्र चाहे जितनी हो मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। दरअसल, अभी उन माताओं को मातृत्व अवकाश मिलता था, जो तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं।

- **बच्चा गोद लेने पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव**– सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जो मातृत्व अवकाश के लाभ को केवल अडॉप्ट माताओं तक ही सीमित रखता था। जब बच्चा तीन महीने से कम आयु का हो। अदालत ने कहा कि जो महिला कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेती है, या किसी बच्चे को जन्म देने वाली मां को सौंपती है, वह बच्चे को गोद लेने वाली मां या बच्चे को जन्म देने वाली मां को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होगी।

- अयोध्या में श्रीरामयंत्र करेंगी स्थापित, यूपी में तीन दिन रहेंगी

संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मथुरा (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में संत प्रेमानंदजी महाराज से मिलने आ रही हैं। वह 19 से 21 मार्च तक तीन दिन यूपी में रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगी। श्रीरामयंत्र स्थापित करेंगी। मथुरा- वृंदावन में इस्कॉन और प्रेम मंदिर सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाएंगी। 20 मार्च को राष्ट्रपति संत उड़िया बाबा के निर्वाण दिवस पर उनके आश्रम पहुंचकर समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। संत उड़िया बाबा की जन्मस्थली ओडिशा है। राष्ट्रपति मुर्मू भी वहीं की रहने वाली हैं। राष्ट्रपति का दौरा इसलिए भी खास है, क्योंकि 19 मार्च को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है,उसी दिन द्रौपदी मुर्मू रामनगरी पहुंचेंगी।

- **राम मंदिर के दूसरे फ्लोर पर स्थापित होगा यंत्र**– श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित किए जाने वाले दिव्य श्रीराम यंत्र को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस यंत्र की स्थापना मंदिर के दूसरे तल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराई जाएगी। प्राण–प्रतिष्ठित इस यंत्र का पूजन रामलला की प्राण–प्रतिष्ठा के साथ ही नियमित रूप से राम मंदिर में किया जा रहा है। अब इसे औपचारिक रूप से मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित किया जाएगा। करीब 150 किलोग्राम वजन वाले इस श्रीराम यंत्र पर सोने की परत चढ़ाई गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

गेंहू पर चालीस रूपए बोनस को कैबिनेट की मिली मंजूरी

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4 हजार 525 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर 40 रूपये प्रति क्विंटल के मान से बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4-लेन एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2-लेन ऐलिवेटेड कॉरीडोर के निर्माण के लिए 945 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके साथ रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 228 करोड़ 42 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इसी तरह मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग का नाम गौपालन एवं पशुपालन किये जाने की भी स्वीकृति दी है।

निर्णय अनुसार उपार्जित गेहूं में से भारत सरकार द्वारा स्वीकार न की जाने वाली सरप्लस मात्रा का निस्तारण मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया जाकर इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। किसानों को बोनस राशि का भुगतान विभागीय मद में बजट प्रावधान कराकर तथा सरप्लस मात्रा के निस्तारण व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजनांतर्गत आवंटित बजट से किया जाएगा।

रीवा की पनवार माईक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 228 करोड़ 42 लाख रूपये की स्वीकृति– मंत्रि-परिषद द्वारा रीवा की पनवार माईक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 228 करोड़ 42 लाख रूपयें, सैंच्य क्षेत्र 7350 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से रीवा जिले की जवा एवं त्योंथर तहसील के 37 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति– मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम को वित्त विभाग के अंतर्गत किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। 'मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम' को एमएसएमई से वित्त विभाग को आवंटित किये जाने से राज्य पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 4,525 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4 हजार 525 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी (इंद्रा नगर) चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर लंबाई 5.32 कि.मी. के निर्माण कार्य को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए लागल राशि 945 करोड़ 20 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 और जन भागीदारी अंतर्गत विकास हेतु अनुदान योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 7 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। एनडीबी से वित्त पोषण पुल और सड़क निर्माण की योजना की निरंतरता के लिए 50 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6 की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 1543 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-7 की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 1,476 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। शासकीय आवास गृह, विश्राम गृहों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिये 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए के लिए 200 करोड़ 35 रूपये की स्वीकृति दी गई है।

भारतीय सेना के भविष्य की जंग का रोडमैप तैयार

- ईरान युद्ध के बीच बनाई गई है एक नई एआई पॉलिसी
- लीथल एआई ,किलर रोबोट व ड्रोन के झुंड करेंगे हमला

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिकी-इजरायल युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन हो चुका है। दोनों ओर से भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका जैसी ताकत और इजरायल जैसे तकनीक में माहिर देशों के होने के बावजूद इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि, नए जमाने के युद्ध ने अपना रंग-ढंग भी बदल लिया है। ऐसे में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बनाई है, जो पूरी तरह से भविष्य के युद्ध को लेकर तैयार की गई है। भारतीय सशस्त्र सेना के लिए नई एआई पॉलिसी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) पर आधारित है, जिसमें इसके साथ ड्रोन के झुंड, एआई से संचालित होने वाले साइबर अटैक के साथ-साथ प्रिडिक्टिव बैटलफील्ड एनालिटिक्स को भविष्य की लड़ाई के लिए मिलिट्री के लिए मूल क्षमताओं में शामिल किया गया है।

सशस्त्र सेनाओं के लिए विजन 2047 पर आधारित नीति

विजन 2047 के तहत 9 मार्च को घोषित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाएं निकट भविष्य में एक डेडिकेटेड डिफेंस क्लाउड स्थापित करेंगी,जिसमें पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी होगी। इसके लिए एकेडमिया को साथ लेकर साझा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ–साथ इसके कमर्शियलाइजेशन में भी संतुलन बिठाने की पहल की जाएगी। युद्ध में आर्टिफिशिय इंटेलीजेंस, रोबोट का इस्तेमाल। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ–साथ ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जगह रोबोट को उतारने की तैयारी। अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन पर फोकस। करीबी युद्ध में ड्रोन झुंड का व्यापक इस्तेमाल। एआई नीति में एआई साइबर वॉरफेयर का भी जिक्र है। इसमें एआई–संचालित मैलवेयर डिटेक्शन की प्रक्रिया भी शामिल है।

नई पॉलिसी से सशस्त्र सेनाओं की इंटेलीजेंस की क्षमता बढ़ेगी

एआई पॉलिसी के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटेलीजेंस, सर्विलांस और टोह लेने की क्षमताओं में भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल/इंफ्रा–रेड इमेजरी, रडार, सोनार, अकूस्टिक और स्पेस–बेस्ड फीड से प्राप्त तस्वीरों को प्राप्त करके, उनके विश्लेषण की क्षमता हासिल की जानी है।

परिवार के साथ पीएम से मिले वरुण गांधी

- लोकसभा में टिकट कटने के बाद पहली मुलाकात

लखनऊ (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से टिकट कटने के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। साथ में उनकी पत्नी यामिनी और बेटी भी थीं। सूत्रों के मुताबिक, वरुण ने देश के मौजूदा हालात पर पीएम से चर्चा की। उनका मार्गदर्शन लिया। पीएम ने भी वरुण और उनकी पत्नी से हालचाल पूछा और उनकी बेटी को दुलार किया। मुलाकात के बाद वरुण गांधी ने एक्स पर लिखा– आपके व्यक्तित्व में पिता जैसा स्नेह और सुरक्षा का भाव है। आपसे मिलकर यह भरोसा और बढ़ जाता है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टिकट न मिलने के बाद वरुण गांधी सक्रिय राजनीति से दूर थे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 18 मार्च 2026

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

बंगाल में फिर ममता और सुवेंदु की होगी भिड़ंत

● भाजपा नेता ने पिछली बार सीएम को नंदीग्राम में हराया था

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजीपीएम को दी हैं। ममता बनर्जी भबानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। उनका मुकाबला भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि मैं

बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए। मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। ममता ने सेलिब्रिटी चेहरों से दूरी बनाई। जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जताया। 2021 में 15 सेलिब्रिटी को टिकट दिया था। इस बार 2 सेलिब्रिटीज को टिकट मिला है। – लिस्ट में 52 महिलाएं हैं। 47 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। – 40 साल से कम उम्र के 42 उम्मीदवारों को टिकट मिला। – लिस्ट में 95 कैंडिटेट्स एससी/एसटी कैंडीडेंट्स हैं।

लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

● स्पीकर बोले-पोस्टर और एआई से बनीं तस्वीरें न दिखाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के एक सांसद हैं। ये आठ सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज

फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत–चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा।

400 बेगुनाहों की हत्या इंटरनेशनल लॉ कहां है

● बम बरसाने वाले पाकिस्तान पर भड़का अफगानिस्तान का क्रिकेटर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल पर हवाई हमला किया, जिसमें अब तक 400 लोगों ने अपनी जान खो दी। इतना ही नहीं बल्कि 250 लोग चोटिल भी गए। पाकिस्तान की इस हरकत से हर कोई हैरान है।

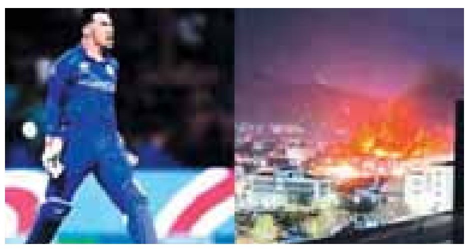

अफगानी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान की इस गिरी हुई हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान द्वारा रमजान के महीने में अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम विस्फोट किया गया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का 30वाँ दीक्षांत समारोह

दीक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी समाज और देश के विकास में सहयोग दें और बने जिम्मेदार नागरिक: राज्यपाल पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि आज विक्रम विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर अत्यधिक आनन्द का अनुभव हो रहा है। उन्होंने दीक्षान्त समारोह में उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए सभी के यशस्वी एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि उज्?जैन नगरी में आते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। सम्राट विक्रमादित्?य विश्?वविद्यालय में ही एक विद्यार्थी ने शिक्षा प्राप्?त की और आज वे प्रदेश के मुख्?यमंत्री बने। मंगलवार को राज्यपाल श्री पटेल की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30 वां दीक्षांत समारोह स्?वर्ण जयंती सभागृह सम्पन्न हुआ।

राज्?यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश का राज्?यपाल बनने के अगले ही दिन वे भगवान श्री महाकालेश्?वर के दर्शन के लिए आए और यहीं से उन्?हें प्रदेश के सतत विकास और देश की प्रगति के लिए प्रयासरत रहने की प्रेरणा प्राप्?त हुई। राज्?यपाल श्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि आज दीक्षांत के साथ आप सभी ने समाज के उत्?थान और देश की एकता के लिए शपथ ली है। विश्?वविद्यालय से जो संस्?कार आपको मिले है उन्?हें जीवन भर स्?मरण रखकर कार्य करें। आपके माता-पिता ने आपको शिक्षित करने के लिए बहुत कष्?ट उठाए है इसलिए पढ़ लिखकर अपने माता-पिता की सेवा करें। आप जीवन में कुछ भी बन जाओं परंतु अपने माता-पिता और गुरु के प्रति सदैव आभारी रहना, उनकी सेवा करना। शिक्षित होने का उद्देश्?य मात्र उपाधि अथवा प्रमाण-पत्र पाना नहीं बल्कि समाज और देश की उन्?नति में योगदान देकर एक जिम्?मेदार नागरिक भी बनना है।

भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन को बनाया अपनी शिक्षा स्थली - मुख्यमंत्री - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ज्ञान-विज्ञान और ध्यान के वैश्विक केन्द्र उज्जैन को भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी शिक्षास्थली के रूप में चुना। चौसठ कलाओं और 14 विद्याओं की यह धरती शौर्य के प्रतीक सुशासन के पुरोधा, विक्रम संवत के प्रवर्तक, भारतीय सांस्कृतिक चेतना के रक्षक और न्यायप्रियता के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की कर्मस्थली रही है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण नहीं बल्कि 7 दशकों के उस समर्पण का परिणाम है, जिसने दुनिया को कुशल मानव संसाधन और श्रेष्ठ स्कॉलर सौंपे हैं। विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रमादित्य का नाम जुड़ने से विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों का गौरव बढ़ा है। ऐसे विश्वविद्यालय की उपाधियों से विभूषित होना विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी-लिट), गोल्ड मेडल और स्नातक उपाधियां प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जीवन में सीखने की एक नई शुरुआत है, यह जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पाइंट है। बेहतर जीवन के लिए विद्यार्थियों को सीखने की ललक सदैव बनाए रखना होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश और प्रदेश के समग्र विकास में सहभागी बनेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निवर्हन करते हुए अपने परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ससम्मान उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की परम्परा आरंभ की गई है। यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन और पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जैसी महान विभूतियों की कर्मस्थली रहा है।

कांग्रेस ने ओडिशा में अपने तीन विधायकों को पार्टी से निकाला

● राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की हरियाणा में जारी होगा नोटिस

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं हरियाणा में पार्टी पांच विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। उनकी पत्नी और नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी भी पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। ओडिशा में कांग्रेस ने रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकाला है। इन तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल, दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी।

जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी

दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को मिलेगा नल से शुद्ध जल

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री-मंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में पुनर्गठित कर लागू करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के साथ सेवा आधारित, टिकाऊ और पारदर्शी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मिशन के लिए कुल व्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी।

जल जीवन मिशन 2.0 योजना के पहले ही दिन मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति और पेयजल मंत्रालय से इस संबंध में एमओयू किया, जिसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पेयजल योजना के लिए पाइपलाइन बिछाने से लेकर पूरी अधोसंरचना का निर्माण करना जिससे पेयजल हर ग्रामीण तक पहुंच सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत की साझेदारी से जलापूर्ति और जल संचयन छोटे-छोटे गांव तक पहुँचाना है।

जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी,आर पाटील , जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमन्ना और मध्य प्रदेश की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, प्रमुख सचिव श्री पी. नरहरि सहित केंद्र और राज्य के आला अधिकारी एमओयू के दौरान मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के अनुमोदन के लिए वे प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब हर अंडे पर लिखी होगी एक्सपायरी डेट

● 1 अप्रैल से नियम लागू, योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ (एजेंसी)। अगर आप अंडे खाते हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। बहुत जल्द हर अंडे पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 अप्रैल से अंडे का कारोबार करने वालों के लिए हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अंडों पर वह तारीख भी लिखी हुई मिलेगी, जिस दिन मुर्गी ने उन्हें दिया गया था। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों और मुर्गी पालन करने वालों को अनिवार्य तौर पर इस नियम का पालन करना होगा। आपको बता दें कि अगर मुर्गी के अंडे को लगभग 30 डिग्री

सेल्सियस के सामान्य तापमान पर रखा जाए, तो वह दिए जाने के दो हफ्तों के अंदर खाने के लिए सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर उसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, तो पांच हफ्तों तक उस अंडे को खाया जा सकता है।

गुजरात में यूसीसी की तैयारी

● समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी रिपोर्ट

गांधीनगर (एजेंसी)। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट पेश की है। गुजरात सरकार आज शाम को इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में ही की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर यह बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

खामेनेई की मौत के बाद इजरायल को मिली सबसे बड़ी सफलता

● ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारीजानी को मारा, बड़ा ऐलान

यरुशलम (एजेंसी)। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारीजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। अली लारीजानी ईरान के सुप्रीम नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद

अली लारीजानी ही ईरान को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। इजरायल के रक्षा मंत्री कट्ज ने अली लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायल की सेना ने बासीज पैरा मिलिट्री मिलिशिया के चीफ घोलामरेजा सुलेमानी और उनके डेप्युटी सैयद कारिशी को भी मार दिया है। यही नहीं इजरायली सेना ने ईरानी आईआरजीसी के वायुसेना के चीफ को भी मार दिया है। अली लारीजानी का मारा जाना इजरायल के लिए बहुत बड़ी सफलता है।

● **अली लारीजानी ही चला रहे थे ईरानी की सत्ता**– ईरान के सुप्रीम नेता अली खामेनेई की मौत के बाद अली लारीजानी सबसे मुखर होकर इजरायल और अमेरिका की आलोचना कर रहे थे। हाल ही में लारीजानी तेहरान में एक रैली के दौरान दुनिया के सामने खुलकर आए थे। अली लारीजानी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे थे। ईरान ने मोजतबा खामेनेई को भले ही अगला सुप्रीम लीडर बना दिया है लेकिन इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वह बुरी तरह से घायल हैं।

ईरान-इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और युवक की मौत

● धमाके से पहले ग्रुप वीडियो कॉल पर घरवालों से बात की थी, शव गांव पहुंचा

सीकर (एजेंसी)। ईरान-अमेरिका, इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और बेटे की मौत हो गई। ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार सीकर जिले के विक्रम वर्मा (22) हुए हैं। वह खंडेला के अगलोई गांव के रहने वाले थे। यह घटना 14 मार्च की है। मंगलवार शव गांव पहुंचा। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मौत से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने परिवार वालों से ग्रुप वीडियो कॉल पर बात की थी। उधर, 1 मार्च को नागौर जिले के दलीप की

मिसाइल अटैक में मौत हो गई। दलीप क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर जॉब करता था। 4 मार्च को इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली थी। विक्रम वर्मा 23 फरवरी को मजदूरी के लिए ओमान गया था। वहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सड़क बनाने का काम कर रहा था। हमले से पहले विक्रम ने अपनी मां, मामा, मौसी और बहन से ग्रुप वीडियो कॉल किया था। बात करते समय विक्रम ने कहा था- अच्छी तरह से हूं।

पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, 400 की मौत

● 250 घायल, तालिबान का आरोप-नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए

काबुल (एजेंसी)। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुलअमान, अरजान कीमत, खैरखाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए।

सीजेआई का सुझाव

जज, वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं

फैमिली कोर्ट में काले चोंगे न पहनें वकील और जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि यह बहुत जरूरी है कि फैमिली कोर्ट बच्चों के मन से मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करें। इसके लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में कुछ बदलाव किए जाएं। उन्होंने पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोंगे होने चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जब हम फैमिली कोर्ट के लिए एक नई सोच और अवधारणा बना रहे हैं तो क्या इससे बच्चे के मन में कोई मनोवैज्ञानिक डर पैदा नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट

में पीठासीन जज और वकील यूनिफॉर्म में नहीं आने चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने ये बातें दिल्ली के रोहिणी में एक फैमिली कोर्ट की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट में आप सभी के लिए हमारे पीठासीन अधिकारी कोर्ट की पोशाक में नहीं बैठेंगे। बार के सदस्य भी काले और सफेद चोंगे में नहीं आएंगे। पुलिस अधिकारी भी वर्दी में नहीं आएंगे, क्योंकि यह पूरा माहौल बच्चों के मन में डर पैदा करता है, खासकर तब जब वे किसी भी व्यवस्था के सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। हर कोई कोर्ट आना नहीं चाहता। जब हम सुधारों की बात करते हैं और जब हम फैमिली कोर्ट की अवधारणा को विवादों को सुलझाने के एक मंच के रूप में देखते हैं तो यह सिविल संपत्ति विवादों जैसा मामला नहीं है। फैमिली कोर्ट का मकसद मानवीय रिश्तों को सुधारना, उन पर विचार करना और उन्हें ठीक करना है।

पुरस्कार वितरण संपन्न

भोपाल। कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2024-25 में सम्पन्न युवा संसद मंचन, निबंध, वाद विवाद, संसदीय प्रश्न मंच तथा चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण विद्यापीठ के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम डॉ. ए.पी. सिंह, अध्यक्ष, म.प्र. मानवाधिकार आयोग के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम

में डॉ. एन. के. थापक, कुलगुरू, एलएनसीटी विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में संसदीय विद्यापीठ की संचालक डॉ. प्रतिमा यादव ने संसदीय विद्यापीठ की गतिविधियों से परिचित करायाद्य एम. के. राजोरिया, उप संचालक ने आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम संचालन डॉ. अर्चना पाण्डेय, शोध अधिकारी ने किया।

कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 में सम्पन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता किए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लगभग 500 विद्यार्थी/शिक्षक सम्मिलित हुए।

किसानों के नाम पर लूट और धोखा बंद करे सरकार, एमएसपी पर 575 रुपए बोनस दे:कुणाल चौधरी

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल, में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं, बल्कि उनके शोषण का माध्यम बन चुकी हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी सही तरीके से नहीं हो रही है। सरकार ने किसानों को राहत देने के नाम पर 575 प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था, लेकिन मात्र 40 बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि सरकार किसानों को एमएसपी पर 575 बोनस दे और इस 40 रुपए बोनस की धोखाधड़ी को तुरंत बंद करे।

किसानों का असली कल्याण तो यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ जहां हमने गेहूं एवं अन्य फसलों पर लगातार 10 वर्षों की सरकार में 33 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ाने का कार्य किया साथी लगभग 70000 करोड़ का देश के किसानों का कर्ज माफ करने का कार्य किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सुश्री समीक्षा द्विवेदी को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से सुश्री समीक्षा द्विवेदी ने मंत्रालय में अपने माता-पिता के साथ सौजन्य भेंट की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के मित्र श्री श्रीनिवास द्विवेदी की सुपुत्री सुश्री समीक्षा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 56वीं रैंक प्राप्त की है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुश्री समीक्षा द्विवेदी को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सुश्री समीक्षा द्विवेदी ने इस उल्लेखनीय सफलता से रीवा, विंध्य क्षेत्र और पूरे मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सुश्री समीक्षा की यह सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है और यह दर्शाती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प से किसी भी ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है।

एचपीवी टीकाकरण अभियान मध्यप्रदेश में 14 वर्ष की एक लाख से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण पूर्ण

सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेश में 14 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख से अधिक किशोरी बालिकाओं के सफल एचपीवी टीकाकरण पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन तथा सहयोगी संस्थाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर, राजस्थान से इस विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया था। मध्यप्रदेश ने इस अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कर देश में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण वाला राज्य बन गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, राजगढ़ और खरगोन जिलों का इस उपलब्धि में विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में समन्वय स्थापित किया गया और स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत विभाग सहित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 वर्ष आयु की बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बेटियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और शेष पात्र बालिकाओं का टीकाकरण भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

11 महीने में लिया 89 हजार करोड़ का कर्ज

फिर 4100 करोड़ के दो नए कर्ज उठाएगी सरकार, मार्च में ही 16200 करोड़ का लोन

भोपाल (नप्र)। मोहन यादव सरकार मार्च के महीने आज तीसरी बार कर्ज उठा रही है। दो अलग-अलग कर्ज 4100 करोड़ रुपए के लिए जा रहे हैं, जिसका भुगतान सरकार को बुधववार को होगा। इस तरह मार्च में सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 16200 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। तीन मार्च को होली पर 6300 करोड़ रुपए के चार अलग-अलग कर्ज लेने के बाद मोहन यादव सरकार ने 10 मार्च को 5800 करोड़ रुपए के तीन कर्ज लिए थे। वित्त विभाग द्वारा किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार आज फिर दो नए कर्ज ले रही है। पहला कर्ज 2100 करोड़ रुपए का 9 साल और दूसरा 2000 करोड़ रुपए का 15 साल की ब्याज अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसका भुगतान सरकार को बुधवार को होने वाला है। इस तरह मार्च में 16200 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। साथ ही चालू साल में लिया गया कर्ज 89000 करोड़ और सरकार पर कुल कर्ज 5 लाख 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक पहुंच जाएगा।

एमपी शिक्षकों की नौकरी पर संकट ?

बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी समर्थन में आए, केंद्र को लिखी चिट्ठी

भोपाल (नप्र)। एमपी में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। अब इन शिक्षकों के समर्थन में नर्मदापुरम से सांसद दर्शन सिंह चौधरी उतर आए हैं। इनके समर्थन में सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुर्निविचार याचिका दायर करने की मांग की है।

नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखी गई चिट्ठी में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि शिक्षक के रूप में 25 साल से अधिक सेवा दे चुके लोगों की नौकरी पर भी खतरा है। उस समय शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के बनाए गए प्रावधानों के अनुसार हुई थी। अब इनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सभी शिक्षक असमंजस में हैं।

शैक्षणिक परिणामों में हुआ है सुधार

इसके साथ ही सांसद दर्शन सिंह चौधरी अपनी

चिट्ठी में कहा है कि राज्य की शिक्षा में सुधार करने में इनका अहम योगदान है। इनकी वजह से शैक्षणिक रिजल्ट में भी सुधार हुआ है। हालांकि इनसे पहले बीजेपी के अन्य नेताओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों में भ्रम की स्थिति है। इसे स्पष्ट करें।

क्यों मंडरा रहा है इनकी नौकरी पर खतरा

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। लेकिन आरटीई लागू होने से पहले जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है, वे टीईटी पास नहीं हैं। एससी का यह आदेश शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 के गाइडलाइन से जुड़ा है।

इस आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में पांच साल बचे हैं, उन्हें यह परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी।

विभाग टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी जुटा रही है। डेटा इकट्ठा होने के बाद जुलाई-अगस्त में परीक्षा हो सकती है।

परीक्षा पास करने के लिए दो साल की समय सीमा है। अगर दो बार में पास नहीं करते हैं तो नौकरी से हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एमपी में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब डेढ़ लाख से अधिक है जो टीईटी पास नहीं हैं। अगर परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो नौकरी जा सकती है। ऐसे में शिक्षक संगठन भी इसके विरोध में हैं।

सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले राज्यों में एमपी चौथा स्टेट

पड़ोसी राज्य यूपी-गुजरात में 11 रुपए सस्ता बिक रहा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए पेट्रोल भरवाना देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सोमवार को पेश किए गए ताजा आंकड़ों (11 मार्च 2026 तक) के विश्लेषण से पता चला है कि मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल की कीमतें सबसे अधिक हैं। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.52 प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

राज्य	शहर	पेट्रोल रेट (₹/लीटर)
आंध्र प्रदेश	अमरावती	₹109.74
तेलंगाना	हैदराबाद	₹107.50
केरल	तिरुवनंतपुरम	₹107.48
मध्य प्रदेश	भोपाल	₹106.52
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	₹105.456

एमपी के पड़ोसी राज्यों में 11 रुपए तक सस्ता बिक रहा पेट्रोल- एमपी के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में पेट्रोल केवल 94.69 और गुजरात (गांधीनगर) में 94.70 प्रति लीटर मिल रहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश की राजधानियों में पेट्रोल के रेट को देखें तो करीब 11 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। एमपी से सटे दूसरे पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 99.44 रुपए प्रति लीटर, महाराष्ट्र के मुंबई में 103.54 प्रति लीटर और राजस्थान में 104.72 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है।

भोपाल-इंदौर मेट्रो में सुरक्षा से खिलवाड़?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की एक कंपनी बाहर, तो दूसरी को 1700 करोड़ के काम

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना इस समय नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट की उलझनों के बीच फंस गई है। केंद्र सरकार की सख्त हिदायत के बाद भोपाल-इंदौर मेट्रो से तुर्की की कंपनी एसिस इलेक्ट्रॉनिक का 186 करोड़ का पत्ता तो साफ हो गया, लेकिन एक दूसरी कंपनी 'गुलरमैक एएस' अब भी सिस्टम के भीतर मौजूद है। यह कंपनी करीब 1700 करोड़ रुपए के तीन बड़े पैकेजों पर काम कर रही है, जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की उस चेतावनी की अनदेखी है जिसमें तुर्किये की कंपनियों को तत्काल हटाने को कहा गया था।

गृह मंत्रालय की वो चिट्ठी- मामला साल 2025 के मध्य का है। 7 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर एक गोपनीय पत्र लिखा। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में तुर्किये की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द किए जाएं। यह पत्र 4 जुलाई को एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तक भी पहुंचा। इसके बाद अगस्त 2025 में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) सिस्टम देख रही एसिस इलेक्ट्रॉनिक को तो बाहर कर दिया गया, लेकिन भारी-भरकम बजट वाली गुलरमैक पर मेहरबानी बरकरार रही।

जॉइंट वेंचर की आड़ में सुरक्षा से समझौता?

गुलरमैक एएस अकेले काम नहीं कर रही, बल्कि वह कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में है। जानकारों का कहना है कि इसी साझेदारी को ढाल बनाकर कंपनी अभी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी हुई है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने देश की सुरक्षा को लेकर आगाह किया है, तो क्या जॉइंट वेंचर होने से खतरा कम हो जाता है?

मेट्रो एमडी की सफाई- इस पूरे विवाद पर एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य का तर्क थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि एसिस इलेक्ट्रॉनिक स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, इसलिए उसे हटाना आसान था। गुलरमैक के मामले में वे कल्पतरु के साथ स्वतंत्र समझौता करने की प्रक्रिया में हैं। यानी कोशिश यह है कि तुर्किये की कंपनी का हिस्सा खत्म कर कल्पतरु को पूरा जिम्मा दे दिया जाए, लेकिन जब तक यह कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक संवेदनशील डेटा और साइट्स पर विदेशी कंपनी की पहुंच बनी हुई है।

गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ऐसे में प्रक्रिया चल रही है जैसे बहाने सुरक्षा में बड़ी चूक साबित हो सकते हैं। एक कंपनी के लिए नियम अलग और दूसरी के लिए अलग क्यों?

प्रोजेक्ट से जुड़े एक वरिष्ठ विशेषज्ञ का नाम न छापने की शर्त पर बयान

क्या है ये पूरा विवाद?- तुर्किये के खिलाफ यह कड़ा रुख 'ऑपरेशन सिंदूर' और वैश्विक मंचों पर तुर्किये की भारत विरोधी गतिविधियों के बाद आया है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि मेट्रो जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी कंपनियों की मौजूदगी से डेटा लीक या भविष्य में सिस्टम को हैक करने जैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि केंद्र ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर इन कंपनियों को बाहर रखा जाए।

रात 8 बजे तक सरकारी केंद्रों पर बिकेगा गेहूं

छुट्टी और त्योहार के दिन गेहूं नहीं खरीदेगी सरकार, चार संभाग में एक अप्रैल से खरीदी

भोपाल (नप्र)। राज्य सरकार ने तय किया है कि रबी सीजन में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में एक अप्रैल और बाकी संभागों में 7 अप्रैल से की जाएगी। गेहूं की खरीदी शासकीय कार्य दिवस में सुबह 8 से रात 8 बजे तक की जाएगी। सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का भी फैसला लिया है। गेहूं 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

किसानों के हित में फैसले ले रही मोहन यादव सरकार ने 15 मार्च तक किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब गेहूं खरीदने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि रबी वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने पंजीयन कराया है।

पिछले साल 15 लाख 44 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सबसे अधिक किसान उज्जैन में 123281, सीहोर में 101793 और राजगढ़ जिले में 98537 रजिस्टर्ड हैं। दूसरी ओर अलीराजपुर में 476, बुरहानपुर में 523, पांढुर्णा में 863 और अनूपपुर में 882 सबसे कम किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

एलपीजी संकट के विरोध में किया अनूठा विरोध-प्रदर्शन

कांग्रेसियों ने दुकानदारों को फ्री बांटा कोयला

भोपाल (नप्र)। रसोई और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कथित कमी को लेकर कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रविन्द्र साहू झूमरवाला ने बुधवार को बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में दुकानदारों और आम नागरिकों के बीच कोयले का वितरण किया।

कोयला बांटकर सरकार को बताई गैस की समस्या- रविन्द्र साहू ने कहा कि गैस सिलेंडरों की उपलब्धता नहीं होने से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर कोयला बांटकर सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया गया है।

सरकारी अव्यवस्था के कारण छोटे व्यापारी परेशान- साहू ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की अव्यवस्थित नीतियों के कारण आम जनता और छोटे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडरों की कमी से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी भी प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल दावे और घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।

सिलेंडर की आपूर्ति ठीक करे सरकार- कांग्रेस नेता ने मांग की कि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति तुरंत सुचारु की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जनहित में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस दौरान क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने भी गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर अपनी समस्याएं साझा कीं और नाराजगी जताई।

मप्र में आज से नया सिस्टम...आधे जिलों में असर

भोपाल, इंदौर-ग्वालियर में आंधी-बारिश का अलर्ट; आज गर्मी रहेगी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 18 मार्च से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है। इससे अगले 3 दिन तक प्रदेश के आधे जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी असर दिखेगा। इससे पहले बारिश, आंधी, गरज-चमक तो कहीं बादल छाए रहेंगे।

अभी तीन सिस्टम, लेकिन असर नहीं- मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और एक टर्फ की एक्टिविटी है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं है। इस वजह से

सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी का असर रहा। मंगलवार को भी तेज गर्मी थी।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि 17 मार्च की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को वेस्टर्न डिस्टरबेंस प्रभावित करेगा। जिसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। इसलिए 18, 19 और 20 मार्च को बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की मानें तो इस सीजन मार्च में पहली बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। जिसका असर लगातार 3 से 4 दिन तक बने रहने के संकेत हैं। ये सिस्टम प्रदेश के सभी हिस्सों से गुजरेगा। इस कारण कहीं सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में गर्मी का असर बना रहा। प्रदेश में खरगोन सबसे गर्म रहा।

यहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सिवनी, मंडला, टीकमगढ़, सागर और खजुराहो में पारा 37 डिग्री या इससे अधिक रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में जबलपुर में पारा सबसे ज्यादा 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भोपाल में 35.2 डिग्री, इंदौर में 35 डिग्री, ग्वालियर में 34.1 डिग्री और उज्जैन में 35 डिग्री दर्ज किया गया।

संपादकीय

रास चुनाव: क्रॉस वोटिंग का खेला

जैसी कि आशंका थी, देश में तीन राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों में से कुछ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है और वही हुआ। सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायको ने की। हालांकि विपक्ष ने इसके लिए भाजपा और उसके धन बल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा ने पैसे का लालच दिया तो भी विपक्षी विधायक बिके क्यों? दूसरे, इस चुनाव ने साबित कर दिया कि कांग्रेस नेतृत्व की अपने संगठन पर कोई पकड़ नहीं है। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए शीर्ष स्तर कोई खास प्रयास किए गए हों, ऐसा नहीं लगा। तीसरे, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में यह पहला चुनाव था। जिसमें वो कामयाब साबित हुए हैं। उन्होंने न केवल अपनी सीट जीती बल्कि भाजपा को पांचवीं सीट भी जितवा दी। जिन 11 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ, उनमें से एनडीए ने 9 और कांग्रेस तथा बीजेडी को 1 1 सीट ही मिली, जबकि बिहार में राजद का एकमात्र प्रत्याशी भी हार गया। इससे यह भी साबित हुआ कि चुनाव प्रबंधन में राजद नेता तेजस्वी यादव को अभी काफी कुछ सीखना है। दरअसल बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग ने राजनीतिक समीकरण को हिला दिया और महागठबंधन और बीजद के लिए बड़ा झटका साबित हुई। बिहार में हाईप्रोफाइल ड्रामे के बाद राज्यसभा की पांचों सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। ओडिशा में भाजपा ने तीन सीटें जीतीं, तो एक बीजद के खाते में गई। हरियाणा में एक सीट पर भाजपा और एक पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। बिहार में कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक के मतदान से दूरी बनाने के बाद एनडीए के चार उम्मीदवार सीएम नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, आरएलएम मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर प्रथम वरीयता के मत के आधार पर जीत गए। पांचवें प्रत्याशी शिवेश राम ने द्वितीय वरीयता में बढ़त के आधार पर जीत हासिल की। बिहार में नीतीश और नितिन को जीत के लिए आवश्यक प्रथम वरीयता के 41 मतों की तुलना में 44-44, ठाकुर व कुशवाहा को 42-42 मत मिले। यहां चार सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत पहले तय थी, लेकिन भाजपा ने राजनीतिक गोटियां फिट करते हुए कांग्रेस और राजद के महागठबंधन से पांचवीं सीट भी झटक ली। हैरानी की बात यह है कि जहां ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक ने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया, वहीं आखिरी वक्त में महागठबंधन के चार विधायक 'लापता' हो गए। इनमें एक राजद का भी था। राजद विधायक फैसल अली ने कहा कि उनकी मां बीमार है। इसलिए वोट डालने से ज्यादा उनके लिए मां महत्वपूर्ण है। उधर ओडिशा में कांग्रेस के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। रमेश जैना, दसरथ गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस ने इन तीनो को पार्टी से निकाल दिया है। इनके क्रॉस वोटिंग से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे संसद के उच्च सदन पहुंच गए और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार दत्तेश्वर होता हार गए। यहां कांग्रेस ने बीजेडी को समर्थन देने की घोषणा की थी। लेकिन सोफिया फिरदौस ने अपने विवेक से फैसला किया।

हरियाणा में इनेलो ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के एक विधायक परमवीर सिंह की वोट को अवैध करार दिया गया है जबकि दूसरे कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल जिसके खिलाफ आपत्ति थी उसे वैध करार दिया गया। दो माह बाद रास की कुछ और सीटों के चुनाव होने हैं, इनमें मप्र की तीन सीटें भी शामिल है। आश्चर्य नहीं कि दिग्विजयसिंह का कार्यकाल समाप्त होने से खाली सीट पर भाजपा यहां भी खेला कर दे।

नेपाल में वाद का बोझ घटा, समस्याओं का नहीं

नजरिया

अरविन्द मोहन

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ।

नेपाल के लोगों ने जितना साफ जनादेश दिया है उसे समझने की जरूरत है। वह पुरानी राजनीति को लगभग सीधे नकारने जैसा है। कौन-कौन पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव में हारा और किसने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, यह सूची पर्याप्त बड़ी है। इतना कहने में हर्ज नहीं है कि नेपाली मतदाताओं ने सारे 'वादों' अर्थात विचारधाराओं का नाम लेकर राजनैतिक नौटंकी करने वालों को ठुकराया है। इसमें कम्युनिस्ट खेमे के दल तो हैं ही, दक्षिणपंथी और राजा समर्थक दल भी हैं। एक पार्टी तो सीधे राजतन्त्र की वापसी के नाम पर इस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही थी। एक सीधे चीन समर्थक पार्टी थी।

नेपाल चुनाव और उसके नतीजों की व्याख्या कई तरह से की जा रही है। यह स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वहां जो कुछ दिखा उसकी चर्चा कम हुई। चुनाव की घोषणा होते ही हर बड़े दल में उठापटक हुई और कई टूट-फूट तथा विलय भी देखने में आये। कई दलों ने अपने 'आराध्य' का नाम लेना पाप समझा तो 'नेपाली कांग्रेस' ने नेपाल के 'जेन-जी' आंदोलन और मुख्य ताकत बनकर उभर रही उनकी 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' को देखते हुए नया नेता चुना, हालांकि तब भी पार्टी चारों खाने चित्त हुई। हरेक दल ने नौजवानों को आगे करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन स्थापित पुराना नेतृत्व नतीजों के पहले मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था।

नेपाल के लोगों ने जितना साफ जनादेश दिया है उसे समझने की जरूरत है। वह पुरानी राजनीति को लगभग सीधे नकारने जैसा है। कौन-कौन पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव में हारा और किसने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, यह सूची पर्याप्त बड़ी है। इतना कहने में हर्ज नहीं है कि नेपाली मतदाताओं ने सारे 'वादों' अर्थात विचारधाराओं का नाम लेकर राजनैतिक नौटंकी करने वालों को ठुकराया है। इसमें कम्युनिस्ट खेमे के दल तो हैं ही, दक्षिणपंथी और राजा समर्थक दल भी हैं। एक पार्टी तो सीधे राजतन्त्र की वापसी के नाम पर इस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही थी। एक सीधे चीन समर्थक पार्टी थी।

खुद बालन शाह के मैथिली बयान या मधेशी होने का सवाल भी उठाया गया, लेकिन लगता नहीं कि मतदाता इन बातों से किसी भी तरह प्रभावित हुआ। 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' को दो तिहाई बहुमत का मतलब बहुत बड़ा है और वह नए कानून बनाने से लेकर इस पर्वतीय राष्ट्र की किस्मत बनाने- बिगाड़ने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। उसकी अपनी राजनीति भी है और प्रधानमंत्री बनने जा रहे बालेंदु उर्फ बालेन शाह और पार्टी अध्यक्ष रबी लामछिने के बीच भी दोस्ती चुनाव के पहले ही हुई है। लामछिने के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं।

काठमांडू के मेयर रहे 35 साल के बालेंदु शाह ने अभी तक पर्याप्त समझदारी दिखाई है, लेकिन एक शहर के शासन और नेपाल के शासन में फरक है। उम्मीद करनी चाहिए कि उनका उत्साह और नई ऊर्जा इस जबाबदेही को बहुत बढ़िया ढंग से पूरा करने में मदद देगी। चुनावी वायदों का पिटारा काफी बड़ा है, लेकिन आँख से दिखती मुश्किलों का पहाड़ वास्तविक पहाड़ों से कम ऊंचा नहीं है। बालेंदु शाह के साथ किसी वाद का तमगा नहीं है, ना ही उन्होंने इस तरह के 'फार्मूले' वाले ज्यादा वायदे किए हैं। वे विचारधारा से मुक्त होंगे, हालांकि 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' का मतलब किसी किस्म की मूल्यगत निष्ठा से स्वतंत्र होना नहीं है।

बेरोगजारी, गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंध या लूट, भारत और चीन जैसे दो बड़े पड़ौसी देशों के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ने की चुनौती और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ही दिखी कमजोरियों को दुरुस्त करने का काम इतना बड़ा है कि इन पड़ौसियों से किसी किस्म की होड लेने या दांव-पेंच दिखाने की फुरसत नहीं होगी। अभी तक लोकतान्त्रिक व्यवस्था से चुनी गई अधिकांश सरकारों ने नेपाल की खास भौगोलिक स्थिति का लाभ अपने स्वार्थ साधने में किया है।

इस बार नेपाली राजनीति के तीन सूरमा - केपी ओली, शेरबहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल उर्फ 'प्रचंड' एकदम हाशिये पर आ गए हैं - देउबा को तो उनकी पार्टी 'नेपाली कांग्रेस' के नए नेताओं ने ही घर बैठा दिया तो ओली की बुरी पराजय हुई। 'प्रचंड' जरूर चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर भी नहीं रह पाई। यह जगह गिरते पड़ते 'नेपाल कांग्रेस' को ही मिली है। फिर बाबूराम भट्टराई जैसे पूर्व सहयोगी के अलग दल बनाने से भी 'प्रचंड' की पार्टी कमजोर हुई है। संभव है, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां फिर से एकजुटता का स्वर बुलंद करें, लेकिन दुनिया में साम्यवाद की हालत और नेपाल में कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा सत्ता संभालने का बुरा अनुभव लोगों को उन पर फिर विश्वास का मौका देगा, यह कहना जल्दबाजी होगी।

ऐसे बड़े और साफ जनादेश के बाद बालेंदु शाह के लिए तात्कालिक राजनैतिक चुनौतियां तो कम होंगी, लेकिन उनको वापस लौटने में देर नहीं लगती। जिस तरह लोगों ने पुरानी राजनीति को ठुकराया है वैसा ही बदलाव एक अन्य मामले में दिखता है। केपी ओली और उनकी पार्टी की हार उनकी मौकापरस्त राजनीति के साथ नेपाल की राजनीति में चीनी दखल की कूटनीति को नकारना भी है। सौभाग्य से इस बार भारत या किसी भारतीय दल की तरफ से कोई ज्यादा नुकसानदेह बयानबाजी या बकवास नहीं की गई। बालन शाह का एकाध भारत विरोधी बयान चलाने की कोशिश हुई तो यह तथ्य आने में देर नहीं हुई कि वह किसी और चीज/गलती की प्रतिक्रिया थी।

नए आदमी के लिए राजकाज भी कोरे पन्ने के साथ शुरू हो तो अच्छा रहता है, लेकिन मुख्य मसला देसी ही रहने वाला है क्योंकि नेपाल के पास अपनी समस्याओं की कमी नहीं है। असली समस्या नेताओं और जिम्मेवार लोगों के भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद की रही है। लोकतंत्र आने के बाद से गिनती के नेताओं का आचरण ही शक-शुबहे से ऊपर रहा है और उनकी चलने नहीं दी गई। इस बार जनता ने ऐसे सारे झमेले किनारे करके बालेंदु शाह को सत्ता सौंपी है। सितंबर में हुई बगावत अपनी समस्याओं के साथ नेताओं के आचरण के खिलाफ थी, इस बात को शाह से बेहतर कौन जानता है?

भारत की कृषि के सामने खड़ी नई चुनौती

ईरान संकट

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक संकटों का असर अंततः आम लोगों की ज़िंदगी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं तक पहुँचता ही है। हाल के घटनाक्रमों ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक, स्ट्रेट् ऑफ़ होमूज़्, को अस्थिर बना दिया है। यह वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग एक चौथाई कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस गुजरती है।ऊर्जा बाजार में किसी भी प्रकार की हलचल का असर केवल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा प्रभाव उर्वरक उद्योग, परिवहन लागत और अंततः कृषि उत्पादन पर पड़ता है।

भारत जैसे देश, जो ऊर्जा और उर्वरकों के कच्चे माल के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय है।ऐसे समय में जब खरीफ 2026 का मौसम सामने है, भारत की कृषि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। भारत को अक्सर कृषि प्रधान देश कहा जाता है और आज भी देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। ऐसे में यदि उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होती है या उनकी कीमतों में तेज़ वृद्धि होती है, तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी खाद्य व्यवस्था और उपभोक्ता बाजार तक पहुँचेगा।

भारत की खेती का एक बड़ा हिस्सा खरीफ मौसम पर आधारित है। धान, सोयाबीन, मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलें इसी मौसम में बोई जाती हैं। इन फसलों के लिए किसानों को विशेष रूप से यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों के उत्पादन में ऊर्जा और आयातित कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है या तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आता है, तो उर्वरकों की लागत बढ़ना लगभग तय है।इसके साथ ही डीज़ल की बढ़ती कीमतें भी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी सिंचाई के लिए डीज़ल पंपों का उपयोग होता है। डीज़ल महंगा होने पर केवल सिंचाई ही नहीं, बल्कि जुताई, कटाई और परिवहन सभी महंगे हो जाते हैं।

खेती की लागत में यह बढ़ोतरी अंततः किसानों की आय को प्रभावित करती है और कई बार इसका असर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई देता है।यह संकट केवल उत्पादन लागत तक सीमित नहीं है। भारत की खाद्य व्यवस्था भी कई महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भर है। विशेष रूप से खाद्य तेलों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता होने पर इन वस्तुओं की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए घरेलू उत्पादन को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना आज पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण सबक को भी याद रखना आवश्यक है। वर्ष 2021 में श्रीलंका ने बिना पर्याप्त तैयारी के रासायनिक उर्वरकों पर अचानक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई, किसानों की आय घट गई और देश को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। इस अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी कृषि परिवर्तन को बिना तैयारी और चरणबद्ध रणनीति के लागू करना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

भारत के लिए आज चुनौती यह है कि वह इस वैश्विक संकट को केवल एक खतरे के रूप में न देखे, बल्कि इसे कृषि व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर के रूप में भी समझे।सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि किसानों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। अक्सर संकट के समय सबसे बड़ी समस्या सूचना के अभाव की होती है। यदि किसानों को समय रहते यह बताया जाए कि उर्वरकों की उपलब्धता सीमित हो सकती है या उनकी कीमत बढ़ सकती है, तो वे अपनी फसल योजना और पोषण प्रबंधन को उसी अनुसार बदल सकते हैं।दूसरा महत्वपूर्ण कदम उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। कई बार किसान परंपरा या सलाह के अभाव में आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। यदि वैज्ञानिक तरीके से मृदा परीक्षण, संतुलित पोषण और जैविक विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए, तो उर्वरकों की कुल मांग को कम किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्थानीय संसाधनों पर आधारित उर्वरक व्यवस्था को मजबूत करना है। गोबर, फसल अवशेष, हरी खाद और अन्य जैविक संसाधनों से बनने वाले कम्पोस्ट और जैविक खाद खेती की लागत को कम करने के साथ-साथ मिट्टी की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर 'जैविक कम्पोस्ट मिशन' जैसी पहल शुरू की जाए तो यह दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकती है।

इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसान संगठनों को मिलकर प्राकृतिक खेती, कम लागत वाली खेती और पोषण प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। किसानों को केवल सलाह देने के बजाय उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण और सफल उदाहरणों से जोड़ना अधिक प्रभावी होगा।अंततः यह भी आवश्यक है कि दलहन और तिलहन उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है और देश की आयात निर्भरता भी कम हो सकती है।हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट हमें यह याद दिलाता है कि कृषि केवल खेत तक सीमित गतिविधि नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई है।यदि समय रहते दूरदर्शिता के साथ कदम उठाए गए, तो यह संकट भारतीय कृषि को अधिक मजबूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर बन सकता है। लेकिन यदि इसे केवल एक अस्थायी समस्या मानकर अनदेखा कर दिया गया, तो आने वाला समय किसानों और देश दोनों के लिए अधिक कठिन हो सकता है।इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि खरीफ 2026 केवल एक कृषि मौसम नहीं, बल्कि भारत की कृषि नीति और खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी की घंटी है।

संकट यदि गहरा है तो प्रतिपक्ष सत्तापक्ष का साथ दे!

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं कि लोकतंत्र की राजनीति में प्रतिपक्ष द्वारा व्यापक जनहित के प्रति विभिन्न मुद्दों को उठाना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होता। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के चलते ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होने लगे जिसका त्वरित समाधान एकाएक संभव न हो, या कि उसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष को धैर्य धारण करना चाहिए और यथासंभव अपने स्तर पर सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। दरअसल कुछ संकट ऐसे भी होते हैं जो हमारे अधिकार और नियंत्रण से परे होते हैं। इस अंतर को समझना प्रतिपक्ष के लिए बहुत जरूरी है।

केवल विरोध के लिए विरोध करना कतई उचित करार नहीं दिया जा सकता। कम से कम राष्ट्रव्यापी संकट के दौर में सत्तापक्ष के साथ-साथ प्रतिपक्ष को भी उत्पन्न संकट से सामना करने के लिए नागरिकों के मनोबल में वृद्धि करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस समय देश-प्रदेश में विभिन्न स्तर पर प्रतिपक्षी नुमाइंदे इस बात को हवा दे रहे हैं कि तेल और गैस के लिए देश में मारामारी हो रही है। जबकि सरकार बार-बार कह चुकी है कि तेल और गैस की आपूर्ति में कहीं से कहीं तक कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद प्रतिपक्ष द्वारा इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर लगातार उछाला जा रहा है।

जिसके चलते आम नागरिकों में यह आशंका बलवती होती जा रही है कि वास्तव में देश के समक्ष तेल एवं गैस का गहरा संकट है। इस धारणा के चलते एक प्रकार से तेल और गैस को लेकर आम नागरिकों में अफरा - तफरी मची हुई है। जिसे प्रतिपक्ष द्वारा एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते चाहे वास्तविक जरूरत हो या नहीं लेकिन आम आदमी में संग्रह वृत्ति पनप रही है। जिसका मिला-जुला परिणाम यह निकल कर आ रहा है कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तेल और गैस की किल्लत के समाचार सुर्खियों में प्रकाशित व प्रसारित किए जा रहे हैं।

हालांकि राष्ट्रीय संकट के दौर में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब सत्तापक्ष का साथ प्रतिपक्ष ने दिया है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में राजनीतिक दल एवं नेताओं की परस्पर कटुता इस कदर बढ़ गई है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी अवसर वे छोड़ना नहीं चाहते। बात-बात पर राजनीति करना अब बहुत आम हो चला है। वरना बीते दौर में उच्च स्तरीय राजनीतिक आदर्श उपस्थित करने की एक लंबी परंपरा रही है। एक पल को यदि यह मान लिया जाए कि वास्तव में देश में तेल और गैस का गहरा संकट है, तो भी क्या प्रतिपक्ष का यह फर्ज नहीं बनता कि वह आम नागरिकों से धैर्य धारण करने की अपील करें और व्यवस्था में सहयोग दें।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी राजनीतिक सौहार्दता के दर्शन आजकल की राजनीति में बहुत दुर्लभ हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या केवल और केवल सत्ता पाने के लिए ही तमाम राजनीतिक दल एवं उसके नेता किसी प्रकार की रणनीति बनाया करते हैं। हालांकि प्रतिपक्ष सत्तापक्ष को घेरने के लिए अवसर की तलाश में रहे, तो इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं की जा सकती। एक अर्थ में यह उसका स्वाभाविक राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन यह कतई आवश्यक नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव एवं तनाव के दौर में देश की जड़ को खोदने का प्रयास किया जाएं। दरअसल ऐसे दौर में विश्व में यह संकेत जाना चाहिए कि हर स्थिति और परिस्थिति से हमें समझौता करना आता है।

प्रतिपक्ष को स्थिति की नजाकत को समझते हुए केवल और केवल अपनी ÷ राजनीति ÷ के लिए हो-हल्ला मचाना उचित नहीं है। दरअसल इस समय सरकार बार-बार आम नागरिकों को आश्वस्त कर रही है कि तेल और गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बावजूद प्रतिपक्ष द्वारा सत्तापक्ष की खाल खिंचाई का सिलसिला लगातार परवान चढ़ रहा है। प्रतिपक्ष द्वारा मचाए गए हो-हल्ले से देश प्रदेश के नागरिकों में एक अजीब खलबली मच गई है। आम नागरिक इस आशंका से ग्रस्त हो गए हैं कि तेल और गैस का संकट इस कदर व्याप्त हो जाएगा कि उनकी सामान्य दिनचर्या बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी।

दरअसल आदमी का मनोविज्ञान ही ऐसा होता है कि कभी-कभी वह अपनी आशंका पर भी पुख्ता विश्वास कर बैठता है। और ऐसे में जब तमाम प्रतिपक्षी नुमाइंदे लगातार शोर मचाएं हुए हो, आम आदमी बुरी तरह डर और सहम कर रह जाया करता है। इसके चलते छोटी से छोटी समस्या भी विशालकाय समस्या प्रतीत होने लगती है। बेहतर यही होगा कि तमाम प्रतिपक्षी दल वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों के चलते उन बातों को अधिक हवा न देवें जिसके चलते आम नागरिकों के अंतर्मन में हाहाकार मच सके। वैसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त तनाव के कम होने या समाप्त होने पर स्थिति खुद ब खुद संभल जाएगी। इसलिए प्रतिपक्ष अनावश्यक शोर शराबा न करें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

श्याम यादव

(लेखक व्यंग्यकार है)

बम वहां, मुसद्दीलाल का सिलेंडर यहां

मियां मुसद्दीलाल को सुबह-सुबह दरवाजे पर खड़ा देख मेरा माथा वैसे ही ठनक गया, जैसे बिना वजह बज उठी। उनके चेहरे की बनावट देखकर साफ था कि आज फिर कोई ऐसा सवाल आने वाला है, जिसका जवाब देने के बाद भी संतोष नहीं मिलेगा। नमस्कार होते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधा मुद्दा दाग दिया सुना आपने, अब हमारे देश में भी गैस की किल्लत होने लगी है! लड़ाई वो देश लड़ रहे हैं और भुगतना हमें पड़ रहा है। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने ही युद्ध की पूरी अंतरराष्ट्रीय पटकथा लिखी हो। मैं कुछ कहता, उससे पहले ही उन्होंने घर के अंदर आवाज लगा दी भाभी जी, आपके यहां तो गैस होगी न, एक कप चाय पिला दीजिएगा।

मुझे समझ नहीं आया कि यह सवाल मुझसे था या समाधान रसोई से निकाला जा रहा था। लेकिन। मुसद्दीलाल का तरीका यही है, जहां समस्या दिखी, वहीं तुरंत उपाय तलाशो, चाहे वह समस्या दुनिया के नक्शे पर क्यों न फैली हो। चाय आने तक उन्होंने अपने तर्कों की गठरी खोल दी। बोले देखिए, ये जो बड़े-बड़े देश हैं न, ये लड़ते कहीं हैं और असर कहीं और होता है। अब बताइए, हमारे चूल्हे का भी क्या कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता है?

मैंने धीरे से कहा दुनिया जुड़ी हुई है मियां, कहीं भी कुछ होता है तो असर पड़ता है। वे तुरंत बोले तो क्या हम भी जुड़कर लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर यह जुड़ाव सिर्फ हमारी रसोई में ही क्यों दिखता है? उनकी बात में गुस्सा कम, हकीकत ज्यादा थी। आम आदमी के लिए दुनिया का नक्शा अब टीवी स्क्रीन या अखबार के पन्नों तक सीमित नहीं रहा, वह धीरे-धीरे उसकी थाली तक उतर आया है। इतने में चाय आ गई।

मुसद्दीलाल ने कप उठाया, एक घूंट लिया और चेहरे पर वही गंभीरता लाकर बोले अभी तो चाय मिल रही है, लेकिन जिस रफ्तार से खबरें आ रही हैं, कल को यह भी खबर बन जाएगी।

मैंने हंसकर बात हल्की करनी चाही आप तो हर चीज को संकट बना देते हैं। वे बिना मुस्कराए बोले संकट मैं नहीं बनाता साहब, संकट खुद आता है। पहले खबर बनता है, फिर बहस बनता है और आखिर में हमारी रसोई में जगह बना लेता है। मैं चुप हो गया। उनकी बातों का तरीका भले ही उलझा हुआ हो, लेकिन निशाना अक्सर सही जगह पर लगता है। वे आगे बोले हम सोचते थे कि दुनिया की लड़ाइयाँ बस खबरों में होती हैं। लेकिन, अब हाल ये है कि उनकी आंच सीधे हमारे चूल्हे तक पहुंच रही है। गैस, जो कभी बस रसोई की चीज थी, अब अंतरराष्ट्रीय मामला बन गई और हम उसके सबसे छोटे गवाह। मैंने सिर हिलाया। सच यही है कि आम आदमी की दुनिया बड़ी सीधी होती है, उसे न भू-राजनीति समझ में आती है, न अर्थशास्त्र। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि चूल्हा जले या न जले।

मुसद्दीलाल अब अपने पूरे रंग में आ चुके थे। बोले सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, बाजार कहता है यह मांग और आपूर्ति का खेल है, और हम कहते हैं कि सिलेंडर समय पर मिल जाए। उनकी इस तीन लाइन की व्याख्या ने पूरी बहस को जैसे समेट दिया। यही तो असलियत है। ऊपर की बातें ऊपर ही रह जाती हैं और नीचे आदमी अपने छोटे-छोटे हिसाब में उलझा रहता है। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया और धीरे से बोले कभी-कभी लगता है कि हम लोग भी किसी युद्ध का हिस्सा हैं। फर्क बस इतना है कि वहां बम गिरते हैं और यहां दाम नहीं, सीधे चूल्हा बुझता है।

मैंने पूछा तो फिर इसका हल क्या है? वे हल्की हंसी के साथ बोले हल, हम लोग हर बार वही करते हैं। थोड़ा कम खर्च, थोड़ा ज्यादा इंतजार और बाकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। उनका यह जवाब सुनकर लगा कि मुसद्दीलाल चाहे जितने बड़े सवाल उठा लें, उनका निष्कर्ष हमेशा आम आदमी की ही भाषा में निकलता है समझौता। वे उठे और बाहर की ओर बढ़े। दरवाज़े तक पहुंचकर जैसे कुछ याद आया, ठिठके और मेरी तरफ देखकर बोले अच्छा, चलता हूँ हमारे यहाँ तो गैस पहले ही खत्म हो चुकी है। सोचा, जब ऊपर वाले देश आग बरसा रहे हैं, तो नीचे वाले कम से कम एक-दूसरे के चूल्हे पर ही गुज़ारा कर लें। आखिर इस लड़ाई में हमारे हिस्से में सिर्फ खाली सिलेंडर ही तो आया है। मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। बाहर सड़क पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर कहीं यह एहसास बैठ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भी आखिरकार हमारे सबसे छोटे चूल्हे तक अपना असर छोड़ ही जाती हैं।

पांच राज्यों के चुनाव और पश्चिम बंगाल की निर्णायक परीक्षा

राजनीति

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। वर्ष 2011 में वाम मोर्चे के लंबे शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था। उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी हुई है और इस बार का चुनाव उसके लिए लगभग 15 वर्षों के शासन की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक राजनीति का एक स्वाभाविक नियम यह है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों को एंटी-इन्कम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। जनता के एक वर्ग में यह भावना बनने लगती है कि अब बदलाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष इसी मनोविज्ञान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

भारत में जब भी कई राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं तो राजनीतिक विमर्श केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा का संकेत भी देने लगता है। चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों–पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी–में विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा के बाद देश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समीकरण बन रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। इसका कारण यह है कि यहां पिछले लगभग डेढ़ दशक से सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस और उसे चुनौती देने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी भाजपा के बीच सीधा और तीखा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। वर्ष 2011 में वाम मोर्चे के लंबे शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था। उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी हुई है और इस बार का चुनाव उसके लिए लगभग 15 वर्षों के शासन की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक राजनीति का एक स्वाभाविक नियम यह है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों को एंटी-इन्कम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। जनता के एक वर्ग में यह भावना बनने लगती है कि अब बदलाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष इसी मनोविज्ञान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा ने पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत की है। कभी राज्य की राजनीति में सीमित उपस्थिति रखने वाली यह पार्टी आज तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को राज्य में उल्लेखनीय सफलता मिली थी और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उसने मजबूत प्रदर्शन करते हुए खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया। यही कारण है कि इस बार भाजपा पूरे आत्मविश्वास के साथ ÷परिवर्तन÷ का नारा दे रही है। पार्टी का मानना है कि राज्य में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक अक्षमता जैसे मुद्दों के कारण जनता बदलाव चाहती है।

किन्तु भाजपा का यह उत्थान मात्र संगठनात्मक कार्य का परिणाम नहीं है – इसके पीछे घुसपैठ का मुद्दा है, जो इस चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के धरातल पर ले जाता है। बांग्लादेश में हिन्दुओं की लगातार हो रही हत्याओं से पश्चिम बंगाल के हिन्दू समुदाय में आक्रोश बढ़ रहा है। इस माहौल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध लोगों की नाराजगी भी तीव्र हुई है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि असम, त्रिपुरा, गुजरात, कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर घुसपैठ नहीं होती – केवल बंगाल की सीमा पर क्यों होती है? उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि न दिए जाने के कारण बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी पूरी नहीं हो पाई। यह आरोप-प्रत्यारोप का खेल केवल शब्द-युद्ध नहीं है – इसके पीछे करोड़ों मतदाताओं की भावनाएँ जुड़ी हैं।

इस चुनाव में एक नया आयाम विशेष सघन पुनरीक्षण – अर्थात् मतदाता सूची के गहन पुनर्निर्माण – का विवाद भी जोड़ता है। यह विवाद रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी मुद्दों को भी पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष बंगाल की राजनीति का एक प्रमुख विषय बन गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच खुला टकराव देखने को मिला। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को बंगाली पहचान और मतदाता अधिकारों के लिए सम्भावित खतरा बताया, जबकि भाजपा का कहना है कि यह प्रक्रिया फर्जी नामों को हटाने के लिए जरूरी है जिनमें कथित तौर पर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, रोहिंग्या और अन्य लोग शामिल हैं। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा और ममता बनर्जी स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं।

ममता बनर्जी निष्क्रिय नहीं हैं। वे एक अनुभवी राजनीतिक योद्धा हैं जो प्रत्येक प्रहार का उत्तर जानती हैं। भाजपा का आरोप है कि पड़ोसी देशों से होने वाली अवैध घुसपैठ ने राज्य की जनसांख्यिकी और सुरक्षा दोनों को प्रभावित किया है। भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की राजनीति से जोड़कर जनता के सामने रखती रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को

राजनीतिक प्रचार बताती है और कहती है कि भाजपा राज्य की सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह घुसपैठ का मुद्दा केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि चुनावी बहस का बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है।

ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनसंपर्क क्षमता और कल्याणकारी योजनाएं मानी जाती हैं। उनकी सरकार ने महिलाओं, गरीबों और ग्रामीण वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जनता का भरोसा अब भी उसके साथ है। पार्टी यह भी कहती है कि भाजपा बाहरी ताकत के रूप में बंगाल की राजनीति में प्रवेश करना चाहती है, जबकि तृणमूल खुद को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का प्रतिनिधि बताती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में केवल विकास या प्रशासनिक मुद्दे ही निर्णायक नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंगाल का समाज अपनी भाषा, संस्कृति और बौद्धिक परंपरा को लेकर काफी सजग माना जाता है। ऐसे में चुनावों के दौरान बंगाली अस्मिता का प्रश्न अक्सर उभरकर सामने आ जाता है। ममता बनर्जी इसी भावनात्मक मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश करती रही हैं, जबकि भाजपा राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मुद्दों को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरती है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार पर कई आरोप भी लगे हैं, जिनमें शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन वितरण से जुड़े विवाद प्रमुख रहे हैं। इन मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। भाजपा का कहना है कि इन घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता अब पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करती रही है। यदि व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं है। इसके परिणाम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। यदि वे एक बार फिर मजबूत जनादेश प्राप्त करती हैं तो उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। वहीं भाजपा के लिए बंगाल में सफलता पूर्वी भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को और विस्तार देने का अवसर होगी।

हालांकि यह भी सच है कि पांच राज्यों के चुनावों में अन्य राज्यों के अपने-अपने राजनीतिक समीकरण हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का पुराना संघर्ष अब भी जारी है, जहां सत्ता के लिए क्षेत्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। केरल में परंपरागत रूप से वाम मोर्चा और कांग्रेस-नीत गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होती है। असम में भाजपा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयास करेगी, जबकि पुडुचेरी में गठबंधन राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रमुख बना हुआ है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल का चुनाव कई कारणों से रोचक और महत्वपूर्ण है। एक ओर लंबे समय से सत्ता में मौजूद नेतृत्व की परीक्षा है, तो दूसरी ओर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रही विपक्षी ताकतों का आक्रामक अभियान। इसके साथ ही पहचान की राजनीति, सामाजिक संतुलन और विकास की बहसें भी इस चुनाव को बहुआयामी बना देती हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। राजनीतिक दल अपने-अपने तर्क, वादे और आरोपों के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन मतदाता अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास भी यही बताता है कि यहां के मतदाता कई बार अप्रत्याशित फैसले लेकर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका देते हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल एंटी-इन्कम्बेंसी, परिवर्तन का नारा या घुसपैठ का मुद्दा ही चुनाव का परिणाम तय कर देगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य के साथ-साथ देश की व्यापक राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पांच राज्यों के चुनावों के बीच भी सबसे ज्यादा निगाहें बंगाल की ओर टिकी हुई हैं, जहां सत्ता, पहचान और राजनीति की बहुस्तरीय लड़ाई एक बार फिर लोकतांत्रिक कसौटी पर परखी जाने वाली है।

लोक माधुरी के गुरीले गायक : बटुक चतुर्वेदी

डॉ. रामवल्लभ आचार्य

6 जुलाई 1932 को विदिशा में पं. मूलचन्द चतुर्वेदी एवं श्रीमती कस्तूरी देवी के सुपुत्र के रूप में जन्मे श्री बटुक चतुर्वेदी ने स्नातक उपाधि अर्जित की। छात्र जीवन से ही आप समाचार पत्र संवाददाता रहे तथा 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य की विधानसभा में सेवा प्रारंभ करने के बाद नया मध्यप्रदेश बनने पर सूचना प्रकाशन विभाग में स्थानांतरित होकर विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 1990 में उच्च पद से सेवा निवृत्त हुए। आप वर्ष 1955 से 1970 तक देश भर के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे। उस समय आप देश के दो अनिवार्य कवियों में से एक रहे किन्तु बाद में स्वास्थ्यगत कारणों से आप मंचीय कवि सम्मेलनों से विमुख हुए।

बटुक चतुर्वेदी साहित्य जगत के ऐसे सृजनधर्मा की संज्ञा है जो जीवन भर अपनी विविधवर्णी रचनाओं से माँ भारती के भंडार को समृद्ध करते रहे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रचुर सृजन किया। कविता, कहानी, गीत, नवगीत, व्यंग्य, उपन्यास, संगीत रूपक और बाल साहित्य के साथ ही लोकभाषा बुन्देली में भी उनका साहित्यिक अवदान उच्चस्तरीय है। उनकी 21 कृतियाँ प्रकाशित हुईं जिनमें आदमी होने का दुख, सुधियों के अमलतास, संवेदन गंध, खूब भरो है मेला, धड़कनों के आसपास, नागफनी के काँटे, कथा श्रीवल्लभ जी की, आप धन्य हैं, हुजूर माई बाप, एक किरण बन जायें, काहू से का कहिये, वरखा - बसंत तथा उपन्यास - हेमन्तिया उर्फ कलेक्टरनी बाई प्रमुख हैं।

6 जुलाई 1932 को विदिशा में पं. मूलचन्द चतुर्वेदी एवं श्रीमती कस्तूरी देवी के सुपुत्र के रूप में जन्मे श्री बटुक चतुर्वेदी ने स्नातक उपाधि अर्जित की। छात्र जीवन से ही आप समाचार पत्र संवाददाता रहे तथा 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य की विधानसभा में सेवा प्रारंभ करने के बाद नया मध्यप्रदेश बनने पर सूचना प्रकाशन विभाग में स्थानांतरित होकर विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 1990 में उच्च पद से सेवा निवृत्त हुए। आप वर्ष 1955 से 1970 तक देश भर के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे। उस समय आप देश के दो अनिवार्य कवियों में से एक रहे किन्तु बाद में स्वास्थ्यगत कारणों से आप मंचीय कवि सम्मेलनों से विमुख हुए।

श्री बटुक चतुर्वेदी की ख्याति हिन्दी और बुन्देली के सशक्त गीतकार के रूप में अधिक रही। आपकी रचनाओं में माटी क? सौंधी महक है इसलिये इन्हें लोक माधुरी के गुरीले गायक के रूप में जाना जाता है। खूब भरो है जमके मेला आपकी लम्बी बुन्देली रचना है जिसमें मेले में पहुँचने की ललक और मेले के अनुपम दृश्यों का सरस वर्णन तो है ही उसके माध्यम से आपने जीवन की क्षणभंगुरता का भी चित्रण किया है। ग्रामीण परिवेश आपकी रचनाओं में बार बार चित्रित हुआ है। दिन आये खजूरा खाबे के, नदिया में बैठ नहाबे के हो अथवा बहुत रसीले आम तुम्हारे गाँव के, हम हो गये गुलाम तुम्हारे गाँव के हो, ये गीत पाठक या श्रोता को बरबस गाँव के माहौल में खींचकर ले जाते हैं। आपके उपन्यास हेमन्तिया उर्फ कलेक्टरनी बाई की नायिका बेड़नी जाति की नर्तकी है जिसके माध्यम से आपने एक स्त्री के हेय दृष्टि से देखे जाने वाले पेशे से निकलकर प्रशासनिक सेवा में चयन होने तक के संघर्ष को नाटकीय ढंग से चित्रित किया है। इस उपन्यास में आपने बुन्देलखण्ड के परिदृश्य को उकेरने हेतु इस अंचल में गाये जाने वाले लोकगीतों की झड़ी लगा दी है।

वैसे आपके हिन्दी गीत और नवगीत भी कमतर नहीं है। एक उदाहरण देखें - मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे पावन द्वार कलंकित करते, शपथ तुम्हारी निर्मलता की, कल से द्वार नहीं आऊँगा।

एक उदाहरण यह भी देखें -

मुस्कानों की खुशबू बाँटो हर दुखिया को टेर के,
बड़े सबेरे मुझसे बोले पीले फूल कनेर के।

एक नवगीत का अंश -

नवयुग के मनमोहक सपने, टँगे हुए हैं उसी अलगनी पर। जिस पर टँगते आये सपने कई पीढ़ियों के।

बटुक जी की कहानियों में युग के संत्रास, सामाजिक विसंगतियों और मानवीय संवेदनाओं के प्रभावी चित्र मिलते हैं तो उनके व्यंग्य दोगले चरित्रों की अच्छी खबर लेते हैं। सन 1990 में मध्यप्रदेश लेखक संघ की स्थापना के बाद अपने प्रदेशाध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने संघ को विस्तार देते हुए 50 इकाइयों की स्थापना की और एक विशाल साहित्यिक संगठन खड़ा किया जिसके माध्यम से आंचलिक साहित्यकारों का सम्मान, भोपाल में विधागत गोष्ठियों के माध्यम से दूरस्थ रचनाकारों को भी साहित्य की मुख्य धारा में लाने तथा विभिन्न सम्मानों द्वारा साहित्यकारों को समादृत करने तथा नये रचनाकारों को प्रोत्साहित करने जैसे विशिष्ट कार्यों द्वारा साहित्यकारों के हितचिन्तक की भूमिला का निर्वहन किया। 18 मार्च 2021 को उन्होंने अंतिम साँस लेकर अपनी जीवन यात्रा को विराम दिया। ऐसे अप्रतिम रचनाकार के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि।

समय सबसे बड़ा न्यायाधीश

विचार

समराज चौहान

लेखिक शोधार्थी हैं।

मनुष्य का जीवन समय की धारा में बहता एक क्षणिक अवसर है। इसी सीमित समय में उसके कर्म, विचार और आचरण का मूल्यांकन होता है। समय हमारे कर्मों की परीक्षा लेता है और उनके अनुसार परिणाम प्रदान करता है। जिसने समय का सदुपयोग किया, वह सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है। वहीं जो समय को व्यर्थ गंवाता है, उसे पछतावा और असफलता का सामना करना पड़ता है। समय कभी किसी को चेतावनी देकर नहीं आता, वह चुपचाप अपना निर्णय सुनाता है। इतिहास साक्षी है कि समय ने अनेक साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। शक्तिशाली राजाओं का अभिमान भी समय के सामने टिक नहीं सका। कभी जो शासक स्वयं को अजेय समझते थे, समय ने उन्हें साधारण बना दिया। इसी प्रकार अनेक साधारण व्यक्तियों को समय ने महानता के शिखर पर पहुँचाया। इससे स्पष्ट होता है कि समय किसी का पक्षपाती नहीं है। वह केवल कर्म और परिस्थितियों के आधार पर परिणाम देता है।

समय एक अदृश्य और अपरिहार्य शक्ति है, जो बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान या सामर्थ्य के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा न्यायधीश है। इसका निर्णय निष्पक्ष और तटस्थ होता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, समय को न तो रोका जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। वह अपनी गति से चलता है और अपने साथ सबको आगे बढ़ा ले जाता है।

मनुष्य का जीवन समय की धारा में बहता एक क्षणिक अवसर है। इसी सीमित समय में उसके कर्म, विचार और आचरण का मूल्यांकन होता है। समय हमारे कर्मों की परीक्षा लेता है और उनके अनुसार परिणाम प्रदान करता है। जिसने समय का सदुपयोग किया, वह सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है। वहीं जो समय को व्यर्थ गंवाता है, उसे पछतावा और असफलता का सामना करना पड़ता है। समय कभी किसी को चेतावनी देकर नहीं आता, वह चुपचाप अपना निर्णय सुनाता है।

इतिहास साक्षी है कि समय ने अनेक साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। शक्तिशाली राजाओं का अभिमान भी समय के सामने टिक नहीं सका। कभी जो शासक स्वयं को अजेय समझते थे, समय ने उन्हें साधारण बना दिया। इसी प्रकार अनेक साधारण व्यक्तियों को समय ने महानता के शिखर पर पहुँचाया। इससे स्पष्ट होता है कि समय किसी का पक्षपाती नहीं है। वह केवल कर्म और परिस्थितियों के आधार पर परिणाम देता है।

समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति जीवन में अनुशासन और नियमितता अपनाता है। वह प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। विद्यार्थी यदि समय का सही उपयोग करे तो वह ज्ञान अर्जित कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। किसान समय पर बीज बोए और फसल की देखभाल करे तो उसे भरपूर उत्पादन मिलता है। व्यापारी समय की मांग को समझकर निर्णय ले तो उसे लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समय की भूमिका निर्णायक होती है।

समय हमें धैर्य का पाठ भी पढ़ाता है। कठिन परिस्थितियाँ सदैव स्थायी नहीं रहतीं। दुःख का समय बीत जाता है और सुख का समय भी अधिक देर तक नहीं ठहरता। यही जीवन का चक्र है। यदि मनुष्य दुःख में धैर्य रखे और सुख में विनम्रता बनाए रखे, तो वह संतुलित जीवन जी सकता है। समय का यही संदेश है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है।कभी-कभी मनुष्य अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि उसका सामर्थ्य सीमित है। वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, परंतु समय उसे उसकी वास्तविकता का बोध करा देता है। समय का न्याय बहुत शांत और गहरा होता है। वह तुरंत दंड या पुरस्कार नहीं देता, परंतु जब देता है तो वह स्थायी और प्रभावशाली होता है। इसलिए कहा जाता है कि समय का न्याय सर्वोपरि है।

समय के साथ चलना ही जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। जो अतीत में ही उलझा रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। समय हमें सिखाता है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान का सदुपयोग ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है।समय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह हमें अनुभव प्रदान करता है। अनुभव ही मनुष्य को परिपक्व बनाता है। समय के साथ-साथ व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और समझ में परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था की सरलता, युवावस्था का उत्साह और वृद्धावस्था की गंभीरता–ये सभी समय की देन हैं। इस प्रकार समय जीवन के प्रत्येक चरण को आकार देता है।

यदि हम अपने जीवन में समय का सम्मान करें, तो हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। समय पर कार्य करना, समय पर निर्णय लेना और समय पर अवसर को पहचानना–ये सभी सफलता की कुंजी हैं। जो व्यक्ति टालमटोल करता है, वह अवसर खो देता है। समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए प्रत्येक क्षण का मूल्य समझना आवश्यक है।समय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल कार्य में ही नहीं, बल्कि विश्राम, परिवार और आत्मचिंतन के लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम समय का संतुलित उपयोग करते हैं, तब जीवन में समरसता आती है। अन्यथा असंतुलन तनाव और असंतोष का कारण बनता है।

समय की गति निरंतर है, परंतु उसका प्रभाव गहरा और स्थायी है। वह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा। यही समय का न्याय है। यह न्याय न किसी अदालत में होता है और न किसी लिखित आदेश के माध्यम से, बल्कि जीवन की परिस्थितियों और परिणामों के रूप में प्रकट होता है।अतः यह स्पष्ट है कि समय सबसे बड़ा न्यायधीश है। वह निष्पक्ष, तटस्थ और अडिग है। उसके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमें चाहिए कि हम समय का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। समय के साथ चलना ही जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो समय को समझता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है।

विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत 19 मार्च को जिला मुख्यालयों में सूर्य उपासना कार्यक्रम

धार। मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष प्रतिपदा एवं विक्रम संवत् 2083 के शुभारंभ के अवसर पर 19 मार्च को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पूर्वान्ह सूर्य उपासना कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, इस आयोजन के अंतर्गत परंपरानुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन के शिखर पर स्थापित किए जाने वाले ब्रह्मध्वज को जिले के प्रमुख मंदिरों एवं स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत ''सम्राट विक्रमादित्य'' विषय पर नाट्य प्रस्तुति का मंचन भी किया जाएगा। निर्देशानुसार, 19 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे सभी जिला मुख्यालयों में सूर्य उपासना कार्यक्रम आयोजित होंगे। धार में यह कार्यक्रम पीजी कॉलेज सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, भोपाल द्वारा ''सम्राट विक्रमादित्य'' नाट्य मंचन हेतु नाट्य एवं कला दल विभिन्न जिलों में अपनी प्रस्तुति देंगे।

घुमंतू जनजाति के लिए प्रस्तुत विधेयक वरदान साबित होगा - डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष -श्याम नायक

● जताई आशा विधेयक अतिशीघ्र कानून का रुप लेगा

धार। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण द्वारा संसद में 13 मार्च को प्रस्तुत विधेयक घुमंतू जनजाति के लिए वरदान साबित होगा। यह जानकारी देते हुए डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम नायक ने प्रसन्नता जाहिर की और के लक्ष्मण जी एवं विधेयक के लिए प्रयत्नशील डीएनटी बोर्ड भारत सरकार के सदस्य भरत भाई पटनी का आभार व्यक्त किया है। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने के लिए, ताकि विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जा सके, उनके लिए एक स्थायी संवैधानिक आयोग की स्थापना करने के लिए औपनिवेशिक काल से चले आ रहे 'आदतन अपराधी' वर्गीकरण के निरंतर प्रयोग को निषिद्ध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए। स्थायी संवैधानिक आयोग की स्थापना केंद्र सरकार विधि द्वारा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियों के लिए एक स्थायी संवैधानिक आयोग की स्थापना करेगी। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय होगा, जो अपने कार्यों में स्वतंत्र होगा तथा अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक स्थिति, शक्तियाँ और संरक्षण प्राप्त करेगा। यह विधेयक संविधान में निहित समानता, गरिमा और न्याय के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है तथा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियों के विरुद्ध हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रभावी निराकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस विधेयक के कानून बनने से घुमंतू समाज का शोषण रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह विधेयक अतिशीघ्र कानून का रुप लेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग

पार्षद ने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री के नाम दिया पत्र

आमला – शहर के वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राकेश शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा। आज मंगलवार को जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र बडोनिया को मुख्यमंत्री के नाम दिए पत्र में पार्षद ने लिखा है कि प्रदेश के लगभग 56 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन लेने वाले तमाम बुजुर्ग विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग आदि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की पेंशन वर्तमान में 6 सौ प्रतिमाह है, जो बेहद कम है। वर्तमान हालात को देखते हुए इतनी कम राशि में ऐसे असहाय लोगों का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है। श्री शर्मा ने कहा है कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि तत्काल ही सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की पेंशन प्रतिमाह 2 हजार रुपए जाए। इस मौके पर सोनम, उर्मिला, सुलोचना, देवकी, पार्वती, कुंदन लाल, मनोहर लाल, सुनील कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।

हवाई सेवा मिलने से विन्ध्य देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कारिडोर बनेगा - उप मुख्यमंत्री

भोपाल . विन्ध्य क्षेत्र को आज विकास की नई सौगात मिली। रीवा एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हुई। एलायंस एयरवेज सप्ताह में तीन दिन रीवा से रायपुर और रायपुर से रीवा के लिए 72 सीटर प्लेन की सुविधा शुरू की। रीवा एयरपोर्ट में आयोजित समारोह में हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से शामिल होकर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. के राममोहन नायडू ने हवाई सेवा का शुभारंभ किया। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री जनार्दन मिश्र तथा अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट को केवल दो वर्षों में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। रीवा एयरपोर्ट अपनी प्राचीन गरिमा और वैभव के साथ विकास की उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने रीवा के विकास को नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की खास

आदमी के साथ आम आदमी को भी हवाई जहाज में उड़ने की सुविधा देने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उड़ान योजना और प्रदेश की नई विमान नीति से प्रदेश में एयरपोर्ट का तेजी से विकास हो रहा है। रीवा एयरपोर्ट के विकास और हवाई सेवाओं के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री नायडू तथा उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के सराहनीय प्रयास सफल हो रहे हैं। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल, इंदौर और दिल्ली के बाद अब रायपुर के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। यह विन्ध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ उठाने में भी रीवा सबसे आगे है। पर्यटन के लिए हेली सेवा शुरू करने के साथ आठ नए एयरपोर्ट एवं 20 हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए नागर विमान मंत्री डॉ. के राममोहन नायडू ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट जबरदस्त उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विन्ध्य के सपनों को उड़ान देने का जो कार्य प्रारंभ किया था वह अब मूर्तरूप ले रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विमान सेवा में देश में मॉडल के तौर पर उभर रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रीवा से रायपुर की सीधी उड़ान के लिए उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल हमेशा से प्रत्यनशील रहे हैं। इस हवाई यात्रा के शुरू हो जाने से रीवा के भविष्य के साथ ही आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा व युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि फेयर से फुरसत अभियान 2.0 के तहत रीवा से रायपुर व दिल्ली का वायुयान का किराया फिक्स रहेगा। उन्होंने रीवा वासियों को इस उपलब्धि के लिए ह्रदय से बधाई दी तथा कहा कि रीवा एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा तथा टर्मिनल भवन का विस्तार भी किया जायेगा।

विधायक कार्यालय में भाजपा की दो दिवसीय कार्यशाला का सामापन, कई वक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया

सोहागपुर। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में सोहागपुर में आयोजित दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विधायक कार्यालय,में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वेंद्र मंडलोई जी ने सोशल मीडिया, AI नमो एप एवं सरल एप विषय पर जानकारी दी। क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ विषय पर विस्तार से सारगर्भित उद्बोधन दिया। पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं अंत में रघुवीर राजपूत ने बूथ प्रबंधन एवं मन की बात विषय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पूर्व दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र में संतोष पारीक ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी ने राष्ट्रवाद और सेवा के सिद्धांतों के आधार पर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है।द्वितीय सत्र में जयकिशोर चौधरी ने वैचारिक अधिष्ठान विषय पर जानकारी देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को समझाया और कहा कि भाजपा की विचारधारा अंत्योदय के संकल्प पर आधारित है, जिसमें समाज

के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य निहित है। तृतीय सत्र में दिनेश तिवारी ने कार्य पद्धति एवं कार्यकर्ता संभाल विषय पर मार्गदर्शन देते हुए संगठन की कार्यशैली, अनुशासन और बूथ स्तर पर सक्रियता के महत्व पर प्रकाश डाला।चतुर्थ सत्र में पूर्व जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल ने कार्य विस्तार विषय पर अपने विचार रखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा गांव-गांव तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाना, पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा से जोड़ना तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए उन्हें तैयार करना बताया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सोहागपुर ब्लाक के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं मातृशक्ति उपस्थित थे। उक्त आशय की जानकारी भाजयुमो के जिला पदाधिकारी अभिनव पालीवाल ने दी।

एसडीएम ने किया निरीक्षण

व्यवसायिक घरेलू गैस के दो प्रकरण दर्ज

सोहागपुर। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने विगत दिवस नर्मदापुरम जिले के एसडीएम को निर्देशित किया था कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा सप्लाई बाधित न हो एवं एसडीएम निरंतर मॉनिटरिंग करें।इसी तारतम्य में आज समीपवर्ती ग्राम सेमरीहरचंद अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी के नेतृत्व में वहां की दुकानों का निरीक्षण किया। जिसमें में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। दोनों दुकानों के मालिकों पर मामले दर्ज किए गए। जिसमें प्रेम नारायण कुशवाहा के द्वारा एचपी गैस के घरेलू सिलेंडर का एवं रजनी कुशवाहा के द्वारा भारत गैस के घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था। दोनों मामलों का पंचनामा बनाकर सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई। इस अवसर तहसीलदार आर एस झरबड़े आदि साथ थे। अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने समस्त ब्लाक के दुकानदारों को आगाह किया है कि व्यवसायिक दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न करें।

बैतूल-अमरावती स्टेट हाईवे पर चक्काजाम

नीमढाना के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पानी और सडक की मांग पर अड़े

एस. द्विवेदी, बैतूल।

बैतूल-अमरावती स्टेट हाईवे पर भैंसदेही विकासखंड की विजयग्राम पंचायत के नीमढाना गांव के ग्रामीणों ने पेयजल और सडक निर्माण की मांग को लेकर आज मंगलवार की दोपहर को चक्काजाम कर दिया, जिससे वँहा वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नीमढाना गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है और दैनिक जरूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के अलावा गांव की सडकें भी बेहद खराब हालत में हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इन समस्याओं को लेकर कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों

को आवेदन देकर शिकायते भी की, लेकिन अब तक उन्हें पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत कार्यालय में अक्सर ताला लगा मिलता है और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी नाराजगी के चलते कुछ दिन पहले ग्रामीण थ्रैक्टरों में भरकर झल्लार थाने पहुंचे थे और थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा था। थाने में दिए गए इसी आवेदन के द्वारा ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर 17 मार्च को चक्काजाम करने की अनुमति माँगी थी।

एक बोरवेल करवाया, लेकिन स्थायी समाधान की मांग – चेतावनी के बाद प्रशासन ने गांव में एक बोरवेल करवाया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है और पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। साथ ही ग्रामीण सीसी रोड केनिर्माण की मांग पर भी अड़े हुए हैं और मंगलवार को उन्होंने बड़ी संख्या में विजयग्राम बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

वाहनों की लगी लंबी कतारें

ग्रामीणों द्वारा चक्काजाम किए जाने के कारण सडक पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लग गई। सडक पर दोनों ओर यात्री वाहन, लगेज वाहन, ट्रक आदि लम्बे समय तक फंसे रहे। चक्काजाम के चलते भरी दोपहरी में वाहन चालकों को घंटो तक चक्काजाम खुलने का लम्बा इंतजार करना पड़ा। कई वाहन चालक और यात्री, वाहनों में बैठे–बैठे गर्मी से परेशान होते हुए भी देखे गये। हालांकि चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था और ग्रामीणों को समझाईश देकर चक्काजाम खुलवाने का प्रयास किया।

इनका कहना है -

ग्रामीणों ने पानी, सड़क की मांग को लेकर चक्कजाम किया था। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान बताय कि पानी की समस्या के समाधान के लिए बोर कराया गया है। जल्द ही मोटर डाली जायेगी। इसके अलावा जिस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी, वह भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत हो चुकी है। ग्रामीणों ने चर्चा के बाद चक्काजाम समाप्त कर दिया।

भगवानदास कुमरे, तहसीलदार, भैंसदेही

एक साल में देश में बढ़ गई संघ की 3842 शाखाएं

भोपाल। आरएसएस के मध्यभारत प्रान्त में शहरों एवं ग्रामीण जिलों के 2481 स्थानों पर 3842 शाखाएं चल रही हैं। जिनमें महानगर में 37 स्थानों पर 544 शाखाएं एवं ग्रामीण जिलों में 2444 स्थानों पर 3298 शाखाएं चल रही हैं। इसके साथ ही 689 स्थानों पर 736 साप्ताहिक मिलन चल रहा है। शाखाओं द्वारा 271 सेवा उपक्रम किए जा रहे हैं। संघ द्वारा सेवा बस्ती के रूप में चिह्नित 1013 सेवा बस्तियों में से 367 में शाखाएं चल रही हैं। 970 बस्तियों में सेवा कार्यों का संचालन किया जा रहा है और 611 सेवा बस्तियों में स्वयंसेवकों का नियमित संपर्क है। यह जानकारी मध्य भारत प्रान्त के प्रान्त संघचालक अशोक पाण्डेय ने मीडिया से चर्चा में दी। उन्होंने हरियाणा के पट्टीकल्याणा (समालखा) में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुई चर्चा के

बारे में बताया। पाण्डेय ने बताया कि संघ के कार्यकर्ता समाज परिवर्तन के कार्यों में संलग्न हैं। स्वयंसेवकों द्वारा 78 बाल गोकुलम्, 9 अध्ययन केंद्र और 13 मासिक कुटुम्ब मिलन भी चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में समाज की सज्जनशक्ति को साथ लेकर नशामुक्ति और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। लहार जिले के सीगपुरा मण्डल मे व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया गया। प्रत्येक ग्राम मे ग्राम सभा आयोजित की गई। अब तक 80 लोग नशा छोड़ चुके हैं। मदनपुरा ग्राम शराब मुक्त हो गया है। शिवपुरी नगर की केशव शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा प्लास्टिक (डिस्पोजल) मुक्त शाखा क्षेत्र अभियान एक वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया, जिसके सुखद परिणाम दिखायी दे रहे हैं। कई स्थानों पर शाखाओं ने और उनकी प्रेरणा से सामाजिक संगठनों ने बर्तन बैंक प्रारंभ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी हो रहे हैं। सीहोर जिले के जावर खंड की माधव शाखा ने गोवंश के लिए रात्रि विश्राम गृह बनाया है। गाँव हाइवे से लगा है। रात्रि में गाय यहाँ बैठी रहती थी और प्रायः दुर्घटना में घायल या मृत हो जाती थी। गायों के विश्राम गृह से समाज को सीधे जोड़ने के लिए एक घर-एक रोटी का उपक्रम चलाया जाता है।

देश में संघ कार्य का विस्तारः

प्रतिनिधि सभा में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि संपूर्ण देश में पिछले वर्ष 51,740 स्थानों पर 83,129 शाखाएं संचालित थीं जो अब बढ़कर 55,683 स्थानों पर 88,949 शाखाएं हो गई हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 3943 नए स्थान जुड़े हैं और शाखाओं की संख्या 5820 की वृद्धि हुई है।

आगजनी की घटनाओं को लेकर प्रशासन सजग

सोहागपुर। आगजनी की घटनाओं को लेकर प्रशासन सजगता दिखा रहा है।इसी तारतम्य को लेकर नगर पंचायत परिषद सोहागपुर के फायर वाहन को थाना सोहागपुर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सोहागपुर के द्वारा सौंपा गया है। जिसमें फायर फाइटरों की ड्यूटी भी लगाई गई है । वाहन थाना सोहागपुर परिसर में खड़ा रहेंगे । पुलिस को आशंका है कि वर्तमान समय में आगजनी की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है ।किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना होने पर आमजन फायर वाहन में चालक राजेंद्र साहू के मोबाइल नंबर 7566877491 एवं कार्तिक मैहरा 6260121163 एवं सहायक प्रांजुल दीवान 8602567375 से संपर्क कर सकते हैं,थाना सोहागपुर के मोबाइल नंबर 7701052276 अथवा पुलिस सहायता वाहन 112 को भी आगजनी की दुर्घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। आमजन एवं कृषक आगजनी की घटना ना हो ऐसा प्रयास करें। सतर्क रहें ।शासन प्रशासन के ने क्षेत्र के किसानों से आग्रह किया है कि नरवाही न जाएं। ताकि खेतों उर्वरा शक्ति बननी रहे। जिसमें फ़सल का उत्पादन बढ़ता रहे।

संक्षिप्त समाचार

परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई, 14 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर वसूला 2.78 लाख रुपये राजस्व

विदिशा (निप्र)। परिवहन आयुक्त के निर्देशन एवं कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला परिवहन विभाग द्वारा शहर में वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा के नेतृत्व में सागर रोड एवं अशोकनगर रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई। जांच अभियान के दौरान कुल 14 वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 10 वाहनों से शमन शुल्क के रूप में 1,72,200 रुपए तथा मोटरयान कर के रूप में 1,06,153 रुपए वसूल किया गया है। इस प्रकार कुल 2,78,353 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 4 वाहनों के प्रकरणों का निराकरण शेष होने के कारण उन्हें जप्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया है। विभाग के अनुसार जप्त वाहनों से लगभग 2 लाख रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। चेकिंग के दौरान विशेष रूप से यात्री वाहनों एवं डंपरों की जांच की गई। इस दौरान एक गंभीर मामला भी सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश से गुजरात की ओर जा रही एक ऑल इंडिया टूरिस्ट यात्री बस में 40 सवारियों की निर्धारित बैठक क्षमता के विरुद्ध 100 यात्री बैठे पाए गए। इस पर परिवहन विभाग द्वारा बस संचालक के विरुद्ध 20,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए निरंतर की जा रही है छापामार कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, होटलों एवं प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसाय के लिए उपयोग करने वाली दुकानों एवं संस्थानों की जांच कर उपयोग किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भैरूंदा में जांच के दौरान भैरूंदा स्थित 10 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करते हुए 08 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री प्रकाश यादव एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रेशमा भामोर ने बताया कि जिले में एलपीजी गैंस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देना है अनिवार्य, सूचना नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप पर निर्माण स्थल का पंजीयन विवरण, कर्मचारियों की संख्या, स्थान सहित अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है, जिस पर नियोजक श्रमिकों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे सकते है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों अनुसार किसी भवन या अन्य सनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को स्थल, सुरक्षा उपाय सहित समस्त आवश्यक जानकारी साँझा करना अनिवार्य है। निर्माण स्थलों की जानकारी या सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।सूचना न देने पर निरीक्षण के दौरान नियम उल्लंघन माना जा सकता है और नियोक्ता पर जुर्माना / कार्रवाई भी हो सकती है। अधिनियम के प्रावधानो अनुसार यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना नहीं देता है, तो उसे कारावास; जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना; जो दो हजार रुपए तक अथवा दोनों हो सकता है। विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण स्थल की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर-18002338888 पर भी सम्पर्क कर सकते है। निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं किये जाने पर नागरिक इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी देकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ताओं को अधिकारों और सतर्कता की दी गई जानकारी

विदिशा ,(निप्र)। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर 15 मार्च को कुरवाई के आजीविका भवन में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा, मां सरस्वती की पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार तंतुवाय ने खाद्य विभाग से संबंधित जानकारी साझा करते हुए उपभोक्ता दिवस के महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं नापतौल निरीक्षक राजीव पांडे ने उपभोक्ताओं को तौल संबंधी सतर्कता बरतने और सही माप-तौल की जांच करने के बारे में जानकारी दी। विद्युत विभाग के एआरओ अभिषेक मिश्रा ने बिजली बिल से संबंधित समाधान योजना के बारे में विस्तार से बताया और उपभोक्ताओं को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुदेशिया खान ने मिठाई और किराना दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं के अधिकार और खाद्य पदार्थों के परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान सीताराम सैनी ने उपभोक्ता अधिकार दिवस के महत्व पर अपने विचार रखते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की अपील की। श्री सुरेंद्र सिंह दांगी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए उपभोक्ताओं से खरीदारी के समय बिल अवश्य लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री बैजनाथ सिंह ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपलब्ध विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बरवाई इंडेन ग्रामीण वितरक, आरती फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप, नापतौल विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा विद्युत विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका कार्यक्रम में उपस्थित 150 से अधिक उपभोक्ताओं और अतिथियों ने अवलोकन किया। इसी अवसर पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विषय पर आधारित निबंध लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन सांदीपनि विद्यालय कुरवाई में किया गया था। निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 7 की इंशा परवीन ने प्रथम, जोया खान ने द्वितीय तथा परिधि सेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कक्षा 6 की आराध्या दीक्षित ने प्रथम, रिद्धि पंथी ने द्वितीय तथा निगहत बी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं को मंच से मुख्य अतिथियों द्वारा क्रमशः प्रथम पुरस्कार 1000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 750 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 500 रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नर्मदापुरम रिजॉर्ट के डिस्प्ले में रखे थे वन्यजीवों के अंग

मैनेजर और नेचुरलिस्ट गिरफ्तार

नर्मदापुरम ,(निप्र)। नर्मदापुरम में सोहागपुर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के मढ़ई क्षेत्र स्थित चर्चित और महंगे फोरसिथ लॉज रिजॉर्ट में वन्यजीवों के अवशेषों की अवैध प्रदर्शनी लगाने के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मैनेजर और नेचुरलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को रविवार को सोहागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में पिपरिया उप जेल भेज दिया गया। वन विभाग के अनुसार, आरोपी मैनेजर निपुण महतो और नेचुरलिस्ट फैज अंसारी हैं। इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

चीतल के सींग, सेही के कांटे और सांप की केंचुली जब्त

7 मार्च 2026 को एसडीएम प्रियंका भलावी के निरीक्षण के दौरान फोरसिथ लॉज के डिस्प्ले में वन्यजीवों के अवशेष प्रदर्शित पाए गए थे। सूचना मिलने पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। बागड़ा बफर जोन के रेंजर विलास डोंगरे ने बताया कि जांच के दौरान रिजॉर्ट के डिस्प्ले से चीतल के सींग, सेही के कांटे और सांप की केंचुली बरामद की गई। इसके बाद 9 मार्च को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

अदालत में पेश कर भेजा जेल

रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेजदीप सासन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 25 मार्च 2026 तक न्यायिक हिरासत में पिपरिया उप जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रतीक तिवारी ने अदालत में तर्क दिया कि वन विभाग ने 7 मार्च को ही वन्यजीव अवयव जब्त कर लिए थे, लेकिन आरोपियों को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया। एक सप्ताह बाद गिरफ्तारी होने से प्रकरण में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। ये चीजें मिलीं- चीतल के 4 सींग, सेही के 4 कांटे, सांप की 2 केंचुली।

40 एकड़ क्षेत्र में फैला रिजॉर्ट, 1 दिन का किराया 35 हजार

मढ़ई के करीब करीब 40 एकड़ क्षेत्र में फैला यह रिजॉर्ट अपनी ग्रामीण शैली के कॉटेज और हाई-स्टैंडर्ड सुविधाओं के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां एक दिन रुकने का खर्च 35 हजार रुपए से अधिक है। सूत्रों के अनुसार, इसकी मालिक अदिति मोदी हैं और बुकिंग का पूरा काम मुंबई से होता है। यहां अकसर बड़ी राजनीतिक हस्तियां और विदेशी सैलानी रुकते हैं।

चैत्र नवरात्रि को लेकर सलकनपुर में सुनिश्चित की जा रही हैं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं

एसडीईआरएफ द्वारा दुकानदारों को दिया गया फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण

सीहोर ,(निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार आगामी 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर सलकनपुर स्थित विजयासन देवी मंदिर पर में आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन एवं मंदिर समिति द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

इसी क्रम में एसडीईआरएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सलकनपुर के दुकानदारों के साथ बैठक कर उन्हें अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान दुकानदारों को आग से बचाव के उपायों और आपात स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि मेला अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार सुनिश्चित की जाएं कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वे सहज व सुव्यवस्थित ढंग से माता विजयासन देवी के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकें।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनी महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सशक्तिकरण का आधार

रायसेन ,(निप्र)। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' लगातार लाडली बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1500 रूपये प्रतिमाह की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। योजना के माध्यम से प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना से महिलाओं को न केवल नियमित सहायता मिल रही है, बल्कि वे अपने परिवार, बच्चों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में भी अधिक आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। रायसेन जिले के गैरतगंज निवासी श्रीमती वर्षा कुशवाह बताती है कि योजना से मिलने वाली राशि ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले स्वयं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें परेशानी होती थी और अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन योजना लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक मजबूती मिली और वे स्वयं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं।

श्रीमती वर्षा कहती हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से उनके घर की व्यवस्था में स्थिरता आई है और बच्चों की शिक्षा में भी वे सहयोग कर पा रही हैं। यह योजना न केवल आर्थिक लाभ देती है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए श्रीमती वर्षा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है।

एमपी किसान एप या जे. फार्म एप के माध्यम से उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करें

हरदा ,(निप्र)। किसान भाई एम.पी. किसान एप या जे.फार्म सर्विस एप के माध्यम से अपनी नजदीकी कस्टम हायरिंग केन्द्रों के संचालक से उन्नत कृषि यंत्रो को किराये पर अनुबंध कर, अपनी कृषि भूमि में उपयोग कर सकते है। उप संचालक कृषि श्री जे.एल. कास्दे ने बताया कि जिले में 171 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित है, जिसमे से 81 कस्टम हायरिंग केंद्र, जे.फार्म सर्विस एप में पंजीकृत है। उन्होने बताया कि किसान भाई जे.फार्म सर्विस एप के माध्यम से सुपरसीडर, रिवर्सिवल प्लाउ, रीपर, रीपर कम बाइन्डर, स्ट्रा रीपर, मल्चर इत्यादि उन्नत कृषि यंत्रों को किराये पर लेकर, नरवाई प्रबंधन कर सकते है, साथ ही उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी होगी जिससे कृषको की आय में वृद्धि हो सकेगी।

तीन दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का समापन

रायसेन (निप्र)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग रायसेन द्वारा आत्मा योजनान्तर्गत तीन दिवसीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का समापन कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा और जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी की उपस्थिति संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री के.पी. भगत, सहायक संचालक श्री दुष्यंत कुमार धाकड़ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं का चहुमुखी विकास किया जा रहा है।

कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर कृषक खेती को लाभकारी बनायें व रायसेन जिले का प्रदेश व देश के स्तर पर नाम रौशन हो सके। जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कृषकों को उन्नत तकनीक के साथ फसल उत्पादन के साथ-साथ सब्जी, फल, फूल, पशुपालन व बकरी पालन जैसी तकनीक का उपयोग कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कुपोषित बच्चों को पोषण किट प्रदान किया गया। कार्यक्रम के तृतीय दिन मध्यप्रदेश राज्य मिलेट योजनान्तर्गत श्री अन्न, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, चेना आदि फसलों के उत्पादन व प्रसंस्करण सम्बन्धी तकनीकी मार्गदर्शन कृषको को दिया गया एवं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बासमती धान के उत्पादन सम्बन्धी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गयी। वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख डॉ. स्वप्निल दुबे द्वारा बताया गया कि रायसेन जिले में बासमती धान लगभग 2,63,000 हैक्टेयर में खेती कर छह लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया जा रहा है। जिले में 31 राइस मिल संचालित की जा रही हैं। जिनमें चावल की ब्रांडिग, श्री भोग, रिवाज एवं रेवा भोग के नाम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा रही है। बाहर के देशों में बासमती धान का जो निर्यात किया जाता है, उसके भौतिक मापदण्ड में नमी की मात्रा 13 प्रतिशत (अधिकतम), कंकड़, मिट्टी इत्यादि की मात्रा नहीं, टूटे दाने की मात्रा 3.5 प्रतिशत अधिकतम, अन्य किस्म के चावल के दाने 4 प्रतिशत अधिकतम व कुकिंग गुणवत्ता में चिपचिपापन नही, पानी सोखने की क्षमता 79 से 83 प्रतिशत तक देखी जाती है। वैज्ञानिक श्री रंजीत सिंह राघव द्वारा रबी फसलों की कटाई के बाद नरवाई में आग न लगाने की सलाह दी गयी, हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद भूसा बनाने एवं रोटावेटर व डिस्क हैरो का उपयोग कर नरवाई को मिट्टी में मिलाने की जानकारी कृषकों प्रदान की गयी। उप संचालक कृषि रायसेन श्री के.पी. भगत के द्वारा बताया गया कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स का ब्लॉक व पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

सीएमएचओ ने सांची में शासकीय अस्पताल का किया निरीक्षण

रायसेन,(निप्र)। जिले में नागरिकों को शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर उपचार मिले, इसके लिए कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएमएचओ डॉ एचएन मांडरे को जिले में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सीएमएचओ डॉ एचएन मांडरे द्वारा गत दिवस प्रातः के समय सांची स्थित शासकीय अस्पताल पहुंचकर उपचार व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एचपीवी वैक्सीनेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टर तथा अन्य स्टाफ की रजिस्टर के अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही सीबीएमओ को एचपीवी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

7 माह बाद भी फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र मामले में एफआईआर नहीं

लोन-बीमा के लिए जिंदा बेटे को मृत बताया, पंचायत-पुलिस में उलझी फाइल

नर्मदापुरम ,(निप्र)। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी स्थित ग्राम पंचायत उमरधा में लोन और बीमा क्लेम के लिए जीवित युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के मामले में 7 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है और अफसरों के बीच फाइल घूम रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते एफआईआर दर्ज होने में लगातार देरी हो रही है और अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जिस उमरधा पंचायत ने यह फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया है, वहां की सरपंच जागृति जूदेव हैं। जागृति जूदेव प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं, जो 2022 में 21 साल की उम्र में निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं और उनकी मां योजनगंधा जिला पंचायत सदस्य हैं।

बीमा और लोन से बचने रची साजिश : उमरधा निवासी राजेंद्र कुशवाह का बेटा नर्मदा ट्रैक्टर ड्राइवर था, जो ढाई साल पहले ट्रैक्टर के नीचे दबने से गंभीर घायल हो गया था। रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वह बिस्तर पर है। नर्मदा ने एलआईसी पॉलिसी ली थी और श्रीराम फाइनेंस से लोन पर ट्रैक्टर खरीदा था। दुर्घटना के बाद किस्तें जमा नहीं हो पा रही थीं, जिसके बाद एक एजेंट के लालच में आकर पिता और चाचा ने साजिश रची।

12 अप्रैल को जारी हो गया था प्रमाणपत्र: पिता राजेंद्र और चाचा हल्के भैया ने 27 मार्च 2025 की रात को बेटे नर्मदा की सामान्य मौत बताते हुए सांडिया घाट पर अंतिम संस्कार की जानकारी दी। मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 10 अप्रैल 2025 को आवेदन दिया गया और तत्कालीन सचिव ओम प्रकाश पटेल के प्रमाणन पर 12 अप्रैल को प्रमाणपत्र जारी हो गया। उनका उद्देश्य बीमा क्लेम लेना और फाइनेंस कंपनी को मृत्यु की सूचना देकर लोन की रकम चुकाने से बचना था।

राजेंद्र कुशवाह पिता | हल्केभैया कुशवाह, चाचा | नर्मदा कुशवाह बेटा

जिला पंचायत सीईओ के निर्देश भी बेअसर: मामला उजागर होने पर बनखेड़ी जनपद सीईओ रीना कुमारिया की जांच टीम ने प्रथम दृष्टया पिता और चाचा को दोषी पाया, जिसके बाद प्रमाणपत्र खारिज कर दिया गया। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन ने ग्राम पंचायत सचिव और जनपद सीईओ को दोषियों पर तत्काल एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे। किसी भी मृत्यु प्रमाणपत्र में आवेदन देने वाले के साथ सत्यापित और जारी करने वाला भी जिम्मेदार होता है, इसलिए तत्कालीन सचिव की भूमिका भी संदेह में है।

पुलिस और पंचायत एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी :

बनखेड़ी जनपद सीईओ रीना कुमारिया ने कहा, 'जीवित का मृत्यु प्रमाणपत्र मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर के लिए पत्र थाने भेजा गया।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन कमियां बताकर पुनः जांच का कहा। हमने फिर दोबारा जांच कर दस्तावेज भेजे। उसमें फिर कमी बताई। इसलिए अब हमने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है। ' वहीं बनखेड़ी थाना प्रभारी विजय सनस ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव साहब सिंह पटेल एफआईआर कराने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, 'दस्तावेज अधूरे होने के कारण आवश्यक कागज लाने को कहा गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया कि दोषी कौन कौन है। '

प्रदेश में घरेलू सिलेंडर की सप्लाई ठीक, कमर्शियल की नहीं

ऑयल कंपनी के डिपो से ट्रकों में लोड, होटल-रेस्टोरेंट को देने के ऑर्डर का इंतजार

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट बरकरार है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जरूर ठीक हुई है, पर कमर्शियल की नहीं। ऑयल कंपनियों से कमर्शियल सिलेंडर ट्रकों में लोड जरूर हुए, लेकिन होटल-रेस्टोरेंट को सप्लाई नहीं की गई। अफसरों को सरकार से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। ऐसे में प्रदेश के 50 हजार होटल और रेस्टोरेंट में सोमवार को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलें। इधर, गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया, भौंरी स्थित डिपो से कमर्शियल सिलेंडर के ट्रक लोड हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट को सिलेंडर देने के आदेश नहीं है। इसलिए सोमवार को अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, पुलिस, सेना-रेलवे कैंटिंग को ही सिलेंडर की सप्लाई की गई है।

महाराष्ट्र में 70 प्रतिशत सप्लाई, एमपी में भी हो- एमपी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया, एसोसिएशन को महाराष्ट्र के उपहार गृहों में 70 प्रतिशत रिलीफ यानी, सिलेंडर दिए जाने के आदेश मिले हैं। एमपी में भी ये आदेश आ सकते हैं। फिलहाल सोमवार को कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया गया। इस कारण प्रदेश के 50 हजार से अधिक होटल और रेस्टोरेंट में समस्या बनी रही। यदि इन्हें भी सिलेंडर मिलेंगे तो यह होटल इंडस्ट्री के लिए 'ऑक्सीजन' मिलने जैसा रहेगा।

पिछले 7 दिन से सप्लाई नहीं होने से भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में होटल-रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इंडक्शन, डीजल भट्?ठी के इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन यह बहुत ही खर्चिला है। इसलिए मेन्यू में बदलाव करने की गाइडलाइन जारी की। सिलेंडर की कमी और ग्राहकों की संख्या कम होने के बावजूद प्रदेश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से कर्मचारियों को नहीं निकाला गया।

घरेलू गैस बुकिंग की 50 प्रतिशत समस्या हुई कम- गैस एजेंसी संचालकों की माने तो प्रदेश में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग की 50 प्रतिशत समस्या खत्म हो गई है। भोपाल में सोमवार को 12 हजार से अधिक बुकिंग आई। हालांकि, पैनिक स्थिति ज्यादा है। यानी, लोग भविष्य में सिलेंडर न मिलने की समस्या आने पर अतिरिक्त सिलेंडर जमा कर रहे हैं। इधर, सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजधानी में ही सोमवार को करीब 50 सिलेंडर जब्त किए गए।

प्रेमिका को कुएं पर बुलाकर शादी का दबाव बनाने लगा प्रेमी, फिर ढाबे पर मिला युवक का शव

निवाड़ी (नप्र)। चर्चित हत्याकांड की गुत्थी निवाड़ी पुलिस ने सुलझा लिया है। साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला त्रिकोणीय प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है। हत्या के बाद युवक का शव एक ढाबे के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मामले को सुलझा लिया है।

नौ मार्च को मिला था शव- वहीं, पुलिस के अनुसार 9 मार्च को शहर के समीप एक ढाबे के पास अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। बाद में पहचान होने पर मृतक का नाम बिजौर गांव निवासी जगदीश कुशवाहा निकला। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग- जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक का केना गांव निवासी ममता कुशवाहा से प्रेम संबंध था और वह उससे मिलने के लिए अक्सर एक कुएं पर आता-जाता था। इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें राजेश दांगी और अजय यादव ने अपराध स्वीकार कर लिया।

चार मार्च को मिलने पहुंचे थे लोग- निवाड़ी पुलिस के मुताबिक 4 मार्च को मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और उस पर विवाह का दबाव बना रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद राजेश दांगी और अजय यादव ने विवाद के बाद उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने शव को ढाबे के पास फेंक दिया था।

पुलिस ने मामले में अजय यादव, राजेश दांगी और ममता कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंधों को लेकर विवाद सामने आया है।

हवा में बढ़ा पोलेन, आंखों पर असर

एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस के केस बढ़े, डॉक्टरों की सलाह- बाहर निकलते समय चश्मा पहनें

भोपाल (नप्र)। शुष्क मौसम और पतझड़ के चलते हवा में पोलेन (परागकण) की मात्रा बढ़ने से शहर में एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हमीदिया और जेपी अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना आने वाले मरीजों में 10 से 15 प्रतिशत यानी करीब 40 से 50 मरीज इसी समस्या से पीड़ित मिल रहे हैं। आंखों में खुजली, जलन और लालिमा की शिकायतों के साथ लोग डॉक्टरों तक पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी

सामान्यतः 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन लापरवाही बरतने पर समस्या गंभीर रूप ले सकती है।

ओपीडी में तेजी से बढ़े मरीज

शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इन दिनों आंखों से जुड़ी एलर्जी के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। हमीदिया अस्पताल और जेपी अस्पताल के नेत्र विभाग में रोजाना आने वाले मरीजों में 10 से 15 फीसदी केस एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस के सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, यह स्थिति हर साल बदलते मौसम के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन इस बार पोलेन की मात्रा अधिक होने से मरीजों की संख्या ज्यादा है।

पोलेन और धूल बन रहे मुख्य कारण

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. निशा मिश्रा के अनुसार, हवा में मौजूद पोलेन, धूल और अन्य सूक्ष्म कण आंखों में जाकर एलर्जी पैदा कर रहे हैं। कई मामलों में यह समस्या आंख में फॉरेन बॉडी (बाहरी कण) जाने के कारण भी हो रही है। इसके चलते आंखों में तेज जलन, सूजन और लगातार पानी आने की समस्या बढ़ रही है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय यह परेशानी अधिक देखी जा रही है।

क्या है एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस

एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस आंखों की एक सामान्य एलर्जी है, जो मुख्य रूप से मौसम बदलने के दौरान होती है। इसमें आंखों की बाहरी परत (कॉन्जंक्टिवा) में सूजन आ जाती है। इससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली व जलन महसूस होती है। कई बार आंखों से पानी भी लगातार निकलता रहता है, जिससे मरीज असहज महसूस करता है।

मुंबई-आगरा हाईवे पर पिकअप पलटी, बच्चे की मौत

20 घायल, 6 की हालत गंभीर, मजदूर जामली से राजपुर जा रहे थे

सेंधवा (नप्र)। मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सेंधवा के समीप ग्राम सालीकला के पास मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 लोग घायल भी हुए। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार है।

यह हादसा सेंधवा के समीप हुआ। पिकअप में 25 से अधिक मजदूर सवार थे, जो जामली लवाणी और आसपास के क्षेत्रों से मजदूरी के लिए राजपुर जा रहे थे। मृतकों में सीतेश (12) पुत्र चपलिया, निवासी जामली शामिल है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

16 को सेंधवा लाए

घायलों में से 16 लोगों को सिविल अस्पताल सेंधवा लाया गया, जहां एक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य 5 घायलों को नारायणदास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज जारी है।

चालक मौके से फरार

घटना के बाद पिकअप का चालक भी मुकेश से फरार हो गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मजदूरों के परिजन भी पहुंचे हैं। पुलिस को भी सूचना दी गई है पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

घायलों के नाम1. संगीता उगला 22 जामली 2. हुरली कैलाश 40 जामली3. निनला किना 16 जामली4. वीरमा फिना 32 जामली5. लीला बाई जतन 52 जामली6. करून दिनेश 16 जामली7. प्रतिज्ञा सुनील 16 जामली8. संगीता हुबला 16 जामली (जिला अस्पताल रेफर)9. हरकी गुड़िया 20 जामली10. सीत्या चपल्या 12 (मृत) जामली11. रीनका शोभाराम 8 लवाणी 12. सुशीला शोभाराम 40 लवाणी13. बायु कालख्या 17 जामली14. परसी कालख्या 45 जामली15. बीरमा भीना 40 जामली 16. नीरा हादु 26 जामली17. भूरली कैलाश 40 जामली 18. रोशनी गुरलाल 15 लवाणी19. पारू रेवला 15 जामली20. रितेश कैलाश 14 जामली

नापतौल कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी

आरडीएक्स लगाने का ई-मेल आया, पुलिस ने खाली कराया ऑफिस, सर्चिंग की

भोपाल (नप्र)। राजधानी में धमकी भरे ई-मेल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी नगर स्थित नापतौल विभाग के कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल में दावा किया गया कि कार्यालय में ड्रोन के जरिए चार छोटे आरडीएक्स बम लगाए गए हैं, जो मंगलवार दोपहर 2 बजे फटेंगे। मेल में सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकालने की बात भी लिखी गई थी। हालांकि जांच में यह फेक निकला। सूचना मिलते ही एमपी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और विभाग के कार्यालय में सर्चिंग कराई गई। सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर कर दिया गया। एमपी नगर थाना प्रभारी जय हिंद शर्मा ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने पूरे कार्यालय की जांच कराई, लेकिन मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला।

बम स्क्वाड ने जांच की

फिलहाल पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। कार्यालय में एक दिन पहले भी इसी तरह का एक मेल आया था, जिसमें पुलिस की तलाशी तकनीकों की जांच करने की बात कही गई थी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच कर रही है।

1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू-मर्सिडीज कंटेनर से उतार 757 किमी दौड़ाईं

भोपाल से विशाखापट्टनम भेजी जा रही दोनों लग्जरी कारें, अब चुकाने होंगे 2.40 लाख

भोपाल (नप्र)। भोपाल से विशाखापट्टनम भेजी जा रही दो लग्जरी कारों-बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को कंटेनर में सुरक्षित पहुंचाने के बजाय रास्ते में उतारकर सैकड़ों किलोमीटर तक चलाने का मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल ने दोनों मामलों में लॉजिस्टिक कंपनी डीआरएस दिलीप रोड लाइंस लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने कहा कि ग्राहक की अनुमति के बिना वाहन को कंटेनर से निकालकर चलाना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। दोनों मामलों में कंपनी को परिवहन शुल्क लौटाने के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। बता दें कि यह दोनों गाड़ियां फरवरी 2025 में भोपाल से खरीदी गईं थीं, हाल ही कंज्यूमर आयोग ने इस मामले में फैसला सुनाया है। पहला मामला नेशनल इनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड का है। कंपनी ने अपनी बीएमडब्ल्यू एम340आई एलसीआई एक्सड्राइव शेडो कार को भोपाल से विशाखापट्टनम भेजने के लिए डीआरएस दिलीप रोड लाइंस की सेवाएं ली थीं।

अंतिम यात्रा

हमारी पूजनीय माताजी
श्रीमती कमला तिवारी
(पत्नी स्व. श्री पुरुषोत्तम तिवारी)
का देहावसान मंगलवार दिनांक 17/03/2026 को हो गया है।
जिनकी **अंतिम यात्रा बुधवार 18/03/2026 को प्रातः 10.30 बजे** निवास स्थान - ई-408, ओल्ड मिनाल रेसीडेंसी, मोगली पार्क के पास, जे.के. रोड, भोपाल से **सुभाष नगर विश्रामघाट** के लिए प्रस्थान करेगी।

शोकाकुल
राजेश-कुसुम तिवारी, रवि-भारती तिवारी (पुत्र-पुत्रवधु)
मदन तिवारी (देवर) हरिनारायण जी व्यास, शिवनारायण जी व्यास (भाई)
आदित्य, अमन, नैतिक (पौत्र)
संपर्क - 9893711137, 9893087969

मोनालिसा की नॉर्मल शादी नहीं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद

सुप्रीम कोर्ट वकील नाजिया बोलीं-आतंकी संगठन एक्टिव हुए

भोपाल (नप्र)। कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने इसे सामान्य शादी मानने से इनकार करते हुए इसे 'प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद' बताया है।

खरगोन में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि शरजील इमाम के अपने भाई की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आने के बाद आतंकी संगठन फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका हो सकती है और इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।

नाजिया खान ने कहा- ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं हैं। ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है। इस्लामिक जिहादी रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली लव जिहाद की यह पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 का उल्लंघन किया गया है। हिन्दू सनातन धर्म में विवाह की जो प्रथा होती हैं उनका भी मिसयूज किया गया है।

कहीं न कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि, फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिन्दू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है।अगर हिन्दू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि उसने पहले हिन्दुत्व कबूल किया है। उसे हिन्दुत्व कबूल करना है तब तो वो हिन्दू प्रथा से शादी कर सकता है। यहां पर हिन्दू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हुआ है। हिन्दू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का एक बड़ा क्राइम सामने आ रहा है।

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मंगलवार को मोनालिसा के माता-पिता मंडलेश्वर पहुंचे और डीएसपी श्वेता शुक्ला की शिकायत सौंपी।

शरजील की सभाओं में फरमान की मौजूदगी की जांच हो

शरजील इमाम ने जहां बैठकर एनआरसी-सीएए के खिलाफ स्पीच दी है उस वीडियोज में फरमान की मौजूदगी को ढूंढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मुझे और सनोज मिश्रा दोनों को यह संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग है। जैसी छांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी।

इनसे कोई सभ्य इंसान नहीं निकल रहे

नाजिया ने कहा- ऐसा सूत्रों से पता चला है क्योंकि केरल में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग सनोज भैया के संपर्क में हैं, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेते हैं। लड़कियों तो पार्सल की ही जाती हैं। हम लोग जो इतनी किडनैपिंग के केस देखते हैं बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान बनकर तो निकल नहीं रहा है। मदरसे में यही लव जिहाद वाले कठमुल्ले निकल रहे हैं। हम अपने देश की राष्ट्रपति जो ट्राइबल महिला हैं उनका हस्तक्षेप इस मामले में बहुत जरूरी है क्योंकि हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते। हम मोनालिसा को जिंदा पाना चाहते हैं।

शरजील इमाम की पैरोल के बाद एक्टिव हुए आतंकी संगठन

नाजिया ने कहा- शरजील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी की पैरोल पर बाहर आया है वैसे ही ये जितने भी टैरेरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अभी हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश में छांगुर पीर जलालुद्दीन को देखा कि वो कैसे लव जिहाद की स्ट्रैटजी चला रहा था। नाजिया ने कहा- हमने केजीएन जिमखाने का मामला भी देखा। हमने बस्ती में देखा कि बस्ती में तीन मुसलमान लड़के तीन सौ से ज्यादा लड़कियों के न्यूड फोटो कराकर उनसे प्रॉस्टीट्यूशन कराने का काम भी कराने की कोशिश में लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि केरल की सरकार ऐसे लव जिहाद और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को काम करना चाहिए। और अतिशीघ्र शरजील इमाम की पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए।